






Rayat Shikshan Sanstha's
Karmaveer Bhaurao Patil College,
Vashi, Navi Mumbai
[Autonomous]

Zero Tolerance Policy



Zero Tolerance Policy

Document No: KBPCV/ZTL/PL/01

Prepared By	Reviewed By	Approved By
Dr. Harsha Goyal & Mr. Sandesh Gharge 	Dr. Harshad Jadhav 	Dr. Shubhada Nayak I/C Principal 
Date: 09-04-2023	Date: 17-04-2023	Date: 19-04-2023
Governing Body Approval		
Released By	IQAC	Date:

KBPCV

Table of Contents

Sr. No	Particulars	Page No.
1	Purpose	4
2	Reporting	4
3	Anti-Ragging Committee & Internal Complaint Committee	4
4	Disciplinary action	5
5	Non-Retaliation & Confidentiality	5
6	Compliance	5

Zero Tolerance Policy for Anti-Ragging Committee and Internal Complaint Committee

Purpose:

The purpose of this policy is to establish a zero-tolerance approach to ragging and harassment within our institution. This policy applies to all students, faculty, staff, and visitors to our campus.

Definitions: For the purposes of this policy, ragging is defined as any conduct by a student or group of students that has the effect of teasing, treating, or handling with rudeness any other student, which causes or is likely to cause annoyance, hardship, or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in a fresher or a junior student.

Anti-Ragging Committee: The Anti-Ragging Committee is responsible for ensuring the implementation of the policy and for investigating any complaints related to ragging or harassment. The committee will consist of members from the faculty, staff, and student body. The committee will work as per the guideline given by University Gant Commission and state Government

Internal Complaint Committee: The Internal Complaint Committee is responsible for addressing complaints related to harassment or discrimination based on gender, sexual orientation, religion, race, or any other protected characteristic. The committee will consist of members from the faculty, staff, and student body. The committee will work as per the guideline given by University Gant Commission and state Government

Reporting:

Any student who witnesses or experiences ragging or harassment should immediately report it to the Anti-Ragging Committee or the Internal Complaint Committee. The report can be made in writing or orally. Anonymous complaints will also be accepted.

Investigation and Resolution:

The Anti-Ragging Committee and Internal Complaint Committee will promptly investigate all complaints and take appropriate action. The investigation will be conducted in a fair and impartial manner, and all parties involved will be given the opportunity to present their side of the story.

Disciplinary Action:

Any student found guilty of ragging or harassment will be subject to disciplinary action, which may include suspension, expulsion, or any other appropriate action as determined by the committee. Faculty or staff found guilty of ragging or harassment will also be subject to disciplinary action, which may include termination of employment.

Awareness and Prevention:

The institution will conduct regular awareness programs and workshops to educate students, faculty, and staff about the consequences of ragging and harassment and the importance of maintaining a safe and respectful environment on campus.

Non-Retaliation:

The institution prohibits retaliation against anyone who makes a good faith report of ragging or harassment or who participates in an investigation of such a report.

Confidentiality:

The institution will take all reasonable steps to maintain the confidentiality of the complainant and the accused during the investigation and resolution process.

Review and Revision: The institution will review and revise this policy as necessary to ensure its effectiveness in preventing and addressing ragging and harassment on campus.

Compliance:

Compliance with this policy is mandatory for all students, faculty, staff, and visitors to our campus. Failure to comply with this policy may result in disciplinary action.

Prepared By	Reviewed By	Approved By
Dr. Harsha Goyal- ICC Mr. Sandesh Gharge- CGRC(Anti-Ragging) <i>Handwritten initials</i>	Dr. Harshad Jadhav <i>(Harshad)</i>	Dr Shubhada Nayak I/C Principal <i>Handwritten initials</i>
Date: 09-04-2023	Date: 17-04-2023	Date: 19-04-2023
Governing Body Approval	Date: 24-04-2023	24-04-2023
Released By	IQAC	Date:

Approved By: Dr. Shubhada Nayak, I/C Principal

Handwritten initials
I/C PRINCIPAL
 KARMAVEER BHURAO PATIL COLLEGE
 VASHI, NAVI MUMBAI - 400 703.





भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042023-245095
CG-DL-E-11042023-245095

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]
No. 233]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 11, 2023/चैत्र 21, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 2023/CHAITRA 21, 1945

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023

F.1-13/2022(CPP-II).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2019 के अधिक्रमण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, नामतः:-

1. संक्षिप्त नाम, विनियोग और प्रारंभ:

- (क) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 कहा जाएगा।
- (ख) वे ऐसे सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर लागू होंगे, जिन्हें किसी केंद्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के तहत स्थापित या निगमित गया हो और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के तहत मान्यता-प्राप्त सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों तथा ऐसे सभी सम विश्वविद्यालय संस्थानों पर लागू होंगे जिन्हें तत्संबंध की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो।



(ग) वे शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. उद्देश्य:

किसी संस्थान में पहले से ही नामांकित छात्रों और साथ ही ऐसे संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक छात्रोंकी कतिपय शिकायतों के निवारण के लिए अवसर प्रदान करना और उसके लिए एक तंत्र स्थापित करना।

3. परिभाषा:

(1) जब तक कि इन विनियमों केसंदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क) "अधिनियम" का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) से है;
- (ख) "पीडित छात्र" से अभिप्राय किसी ऐसे छात्र से है जिसे इन विनियमों के तहत परिभाषित शिकायतों के संबंध में किसी मामले अथवा तत्संबंधी किसी मामले में कोई शिकायत हो।
- (ग) "महाविद्यालय" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (1) के खंड (ख) में इस प्रकार से परिभाषित किसी संस्थान से है।
- (घ) "आयोग" से अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है।
- (ङ) "घोषित प्रवेश नीति" का अभिप्राय संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए संस्थान की विवरणिका में प्रकाशित की गई किसी ऐसी नीति से है, जिसमें उसके अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं।
- (च) "शिकायत" का अभिप्राय, और इसमें निम्नवत् के संबंध में किसी पीडितछात्र द्वारा की गई शिकायत (शिकायतें) शामिल हैं, नामतः
- i. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुरूप निर्धारित की गई योग्यता के विपरीत प्रवेश दिया जाना;
 - ii. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के तहत प्रक्रिया में अनियमितताएं;
 - iii. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुरूप प्रवेश देने से इंकार किया जाना;
 - iv. इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप, संस्थान द्वारा विवरणिका का प्रकाशन न किया जाना;
 - v. संस्थान द्वारा विवरणिका में ऐसी कोई जानकारी देना जोकि झूठी या भ्रामक होऔर तथ्यों पर आधारित न हो;
 - vi. किसी छात्र द्वारा ऐसे संस्थान में प्रवेश लेने के प्रयोजन से जमा किए गए किसी दस्तावेज जोकि उपाधि, डिप्लोमा या किसी अन्य पुरस्कार के रूप में हो,उसको अपने पास रख लेना या वापस करने से इंकार करना ताकि ऐसे किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम के संबंध में छात्र को किसी शुल्क अथवा शुल्कों का भुगतान करने हेतु तैयार किया जा सके अथवा मजबूर किया जा सके जिसमें छात्र अध्ययन नहीं करना चाहता हो;
 - vii. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति में निर्धारित राशि से अधिक धनराशि की मांग करना।
 - viii. छात्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रवेश में सीटों के आरक्षण के संबंध में वर्तमान में लागू किसी कानून का संस्थान द्वारा उल्लंघन किया जाना;



- ix. ऐसे किसी संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के तहत अथवा आयोग द्वारा विहित किन्हीं शर्तों, यदि कोई हो तो, के तहत किसी भी छात्र हेतु ग्राह्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का भुगतान नहीं किया जाना अथवा विलम्ब से भुगतान किया जाना;
- x. संस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर में अथवा आयोग द्वारा विहित ऐसे किसी कैलेंडर में विनिर्दिष्ट अनुसूची से इतर परीक्षाओं के आयोजन में अथवा परीक्षा के परिणामों की घोषणा में विलम्ब करना;
- xi. विवरणिका में यथा उल्लिखित अथवा संस्थान द्वारा लागू किसी कानून के किसी उपबंध के तहत यथा अपेक्षित छात्रों की सुविधा प्रदान करने में संस्थान द्वारा विफल रहना;
- xii. छात्रों के मूल्यांकन के लिए संस्थान द्वारा अपनाई गई गैर-पारदर्शी अथवा अनुचित पद्धतियां;
- xiii. ऐसे किसी छात्र को शुल्क के प्रतिदाय में विलंब करना, अथवा इंकार करना जो कि विवरणिका में उल्लिखित समय के भीतर, बशर्ते यह समय-समय पर आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन हो, नामांकन वापस लेता है;
- xiv. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक अथवा दिव्यांग श्रेणियों के छात्रों से कथित भेदभाव की शिकायत;
- xv. प्रवेश दिए जाने के समय जैसा भरोसा दिलाया गया था अथवा प्रदान किया जाना अपेक्षित था के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं किया जाना;
- xvi. छात्र के उत्पीड़न के अन्य मामलों के अलावा जिन पर वर्तमान में लागू किसी कानून के दंडात्मक उपबंधों के तहत कार्रवाई की जानी हो, छात्र का उत्पीड़न किया जाना अथवा उसे निशाना बनाया जाना।
- xvii. संस्थान के कानूनों, अध्यादेशों, नियमों, विनियमों, या दिशा-निर्देशों के विपरीत कोई कार्रवाई किया जाना अथवा शुरू किया जाना; तथा
- xviii. आयोग और/अथवा संबंधित नियामक निकाय द्वारा बनाए गए/जारी किए गए नियमों और/या दिशा-निर्देशों के विपरीत कोई भी कार्रवाई किया जाना अथवा शुरू किया जाना।

(द) "संस्थान" से तात्पर्य विश्वविद्यालय से है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (एफ) में परिभाषित है, एक संस्थान जिसे अधिनियम 3 के तहत विश्वविद्यालय माना गया है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12ए (1) (बी) में परिभाषित एक महाविद्यालय से है।

(ज) "लोकपाल" का अभिप्राय इन विनियमों के तहत नियुक्त लोकपाल से है।

(झ) "विवरणिका" का अभिप्राय और इसमें ऐसा कोई प्रकाशन शामिल है, चाहे वह मुद्रित स्वरूप में अथवा अन्यथा हो, जिसे जनसाधारण (जिसमें ऐसे संस्थान में प्रवेश पाने के इच्छुकों सहित) को एक संस्था से संबंधित निष्पक्ष और पारदर्शी जानकारी प्रदान करने के लिए ऐसे संस्थान अथवा किसी प्राधिकरण अथवा ऐसे संस्थान द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया हो;

(ञ) "छात्र" से अभिप्राय किसी ऐसे संस्थान जिसमें यह विनियम लागू होते हैं, में किसी भी माध्यम से अर्थात् औपचारिक/मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल)/ऑनलाइन से नामांकित किसी व्यक्ति अथवा नामांकित होने के लिए प्रवेश प्राप्ति के इच्छुक से हैं;



- (ट) "छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी)" का अभिप्राय एक संस्थान के स्तर पर इन विनियमों के तहत गठित एक समिति से है; तथा
- (ठ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 2 की खंड (च) में यथा परिभाषित किसी विश्वविद्यालय से है अथवा जहां संदर्भ के अनुसार, तत्संबंध की धारा 3 के तहत इस प्रकार घोषित कोई सम विश्वविद्यालय संस्थान से है।

इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में उनके लिए निर्धारित किए गए हैं।

विवरणिका का अनिवार्य प्रकाशन, इसकी विषयवस्तु तथा मूल्य निर्धारण

- 1) प्रत्येक संस्थान, अपने पाठ्यक्रम या अध्ययन के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश आरंभ करने की तिथि से कम से कम साठ दिन की समाप्ति से पूर्व अपनी वेबसाइट पर एक विवरणिका प्रकाशित और/अथवा अपलोड करेगा, जिसमें इस तरह के संस्थान में प्रवेश लेने के इच्छुक व्यक्तियों और आम जनता की जानकारी के लिए निम्नवत् जानकारी अंतर्विष्ट होगी, यथा;
- (क) प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन के कार्यक्रम के लिए, शिक्षण के घंटों, व्यावहारिक सत्रों और अन्य कार्य के साथ-साथ अध्ययन के कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की सूची सहित उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरण अथवा संस्थान, जैसा भी मामला हो, द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम की व्यापक रूपरेखा;
- (ख) जिस शिक्षा वर्ष हेतु प्रवेश दिए जाने का प्रस्ताव हो, उसके प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन के कार्यक्रम के संबंध में उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सीटों की संख्या;
- (ग) संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विशेष पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन कार्यक्रम में छात्र के रूप में प्रवेश के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा सहित शैक्षिक योग्यता और पात्रता की शर्तें;
- (घ) इस प्रकार के प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया, जिसमें प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के लिए परीक्षा या इम्तहान के विवरण के संबंध में सभी संगत जानकारी और प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क की राशि शामिल है;
- (ङ) किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में अध्ययन करने के लिए ऐसे संस्थान में भर्ती किए गए छात्रों द्वारा देय शुल्क, जमा राशियों और अन्य प्रभारों के प्रत्येक घटक और ऐसे भुगतानों की अन्य निबंधन और शर्तें;
- (च) शास्ति लगाए जाने और संग्रहण किए जाने हेतु नियम/विनियम, विनिर्दिष्ट शीर्ष अथवा श्रेणियां, लगाए जाने वाली शास्ति की न्यूनतम और अधिकतम राशि;
- (छ) ऐसे संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों द्वारा यदि पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम के पूरा होने से पहले अथवा के बाद दाखिला छोड़ दिया जाता है तो छात्रोंको प्रतिदाय किए जाने वाले शिक्षण शुल्क और अन्य प्रभारों का प्रतिशत तथा समय सीमा जिसके भीतर तथा पद्धति जिससे छात्रोंको ऐसा प्रतिदाय किया जाएगा;
- (ज) उनकी शैक्षिक योग्यता शिक्षण संकाय का विवरण, उनकी नियुक्ति का स्वरूप (नियमित/अभ्यागत/अतिथि) और उसके प्रत्येक सदस्य के शिक्षण अनुभव के साथ;
- (झ) भौतिक और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे और छात्रावास तथा इसके शुल्क, पुस्तकालय, चिकित्सालय अथवा उद्योग, जहां छात्रोंको व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना हो, सहित अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी और विशेषरूप से छात्रों द्वारा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने पर प्राप्त होने वाली सुविधाओं का ब्यौरा अंतर्विष्ट हो



(ज) संस्थान के परिसर के भीतर अथवा बाहर छात्रों द्वारा अनुशासन बनाए रखने के संबंध में सभी संगत निदेश और विशेषरूप से किसी छात्र अथवा छात्रों की रैगिंग निषिद्ध करने संबंधी ऐसे अनुशासन को बनाए रखने और उनका उल्लंघन किए जाने के परिणामों और संगत सांविधिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में तैयार किए गए किसी विनियम के उपबंधों का उल्लंघन किए जाने के परिणामों का ब्योरा अंतर्विष्ट होगा; तथा

(ट) आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य जानकारी:

बशर्ते प्रत्येक संस्थान इस विनियम के खंड (क) से (ट) में उल्लिखित जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित/अपलोड करेगा और विभिन्न समाचार-पत्रों और अन्य मीडिया के माध्यम से प्रमुखता से प्रदर्शित करते हुए विज्ञापनों के माध्यम से इच्छुक छात्रों और आम जनता का ध्यान वेबसाइट पर इस तरह के प्रकाशन की ओर दिलाया जाएगा।

2. प्रत्येक संस्थान अपनी विवरणिका की प्रत्येक मुद्रित प्रति का मूल्य निर्धारित करेगा, जोकि विवरणिका के प्रकाशन और वितरण की उचित लागत से अधिक नहीं होगी और विवरणिका के प्रकाशन, वितरण या बिक्री से कोई लाभ अर्जित नहीं किया जायेगा।

5. छात्र शिकायत निवारण समितियां (एसजीआरसी)

(i) संस्थान से संबंधित किसी पीड़ित छात्र की किसी भी शिकायत छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) के अध्यक्ष को संबोधित की जाएगी।

(ii) प्रत्येक संस्थान छात्रों की शिकायतों पर विचार करने के लिए निम्नलिखित संरचना के साथ उतनी संख्या में छात्रों की शिकायत निवारण समितियों (एसजीआरसी) का गठन करेगा, जितने कि आवश्यकता हो सकती है, नमातः

क) एक प्रोफेसर – अध्यक्ष

ख) संस्थान के चार प्रोफेसर/वरिष्ठ संकाय सदस्य- सदस्य के रूप में।

ग) शैक्षिक योग्यता/खेल-कूद में उत्कृष्टता/सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर नामित किए जाने वाले छात्रों में से एक प्रतिनिधि- विशेष आमंत्रित।

घ) अध्यक्ष अथवा कम से कम एक सदस्य का महिला होना चाहिए तथा कम से कम एक सदस्य अथवा अध्यक्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए।

ङ) अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

च) विशेष आमंत्रित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

छ) बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित लेकिन विशेष आमंत्रित व्यक्ति को छोड़ कर तीन का होगा।

ज) एसजीआरसी अपने समक्ष आने वाली शिकायतों पर विचार करते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा।

झ) एसजीआरसी अपनी रिपोर्ट सिफारिशों के साथ, यदि कोई हो, संबंधित संस्था के सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा और उसकी एक प्रति पीड़ित छात्र को, अधिमानतः शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 15 कार्य दिवसों की अवधि के अंदर भेजेगा।

ञ) छात्रों की शिकायत निवारण समिति के निर्णय से पीड़ित कोई भी छात्र इस प्रकार के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है।

6. लोकपाल की नियुक्ति, सेवाकाल, पद से हटाया जाना और सेवा की शर्तें:

(i) प्रत्येक विश्वविद्यालय इन विनियमों के तहत विश्वविद्यालय के छात्रों और महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से जुड़े संस्थानों के छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल की नियुक्ति करेगा।



- (ii) एसजीआरसी के निर्णयों के विरुद्ध की गई अपीलों को सुनने और उन पर निर्णय लेने के लिए लोकपाल के रूप में नामित एक या अधिक अंशकालिक पदाधिकारी होंगे।
- (iii) लोकपाल सेवानिवृत्त कुलपति या सेवानिवृत्त प्रोफेसर (जिन्होंने अधिष्ठाता (डीन)/विभाग प्रमुख के रूप में काम किया हो) होंगे और उनके पास राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालयों/राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों/सम विश्वविद्यालयों या पूर्व जिले में न्यायाधीश के रूप में 10 वर्ष का अनुभव रहा हो।
- (iv) लोकपालनियुक्ति के समय, नियुक्ति से पहले एक वर्ष के दौरानया लोकपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, संस्थान के साथ हितों के टकराव में नहीं होंगे जहाँ उनके व्यक्तिगत संबंध, पेशेवर संबद्धता या वित्तीय हित समझौता कर सकते हैं या उचित रूप से संस्थान के प्रति निर्णय की स्वतंत्रता से समझौता करने के लिए प्रतीत हो सकते हैं।
- (v) लोकपाल को पद ग्रहण करने की तिथि सेतीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाएगाऔर एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
- (vi) सुनवाई का संचालन करने के लिएलोकपाल को संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रति दिनप्रति बैठक के अधार पर शुल्क का भुगतान किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, वे यात्रा पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।
- (vii) कदाचार या दुर्व्यवहार के सिद्ध आरोपों पर विश्वविद्यालय लोकपाल को पद से हटा सकता है।
- (viii) लोकपाल को हटाने का कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि इस संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जांच नहीं कर ली जाती है, जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पद से नीचे के पद का व्यक्ति ना हो, और जिसमें लोकपाल को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो।

7. लोकपाल के कार्यकरण:

- (i) लोकपाल, छात्र द्वारा इन विनियमों के तहत उपबंधित सभी विकल्पों को अपनाने के पश्चात् ही पीडितछात्र की अपील की सुनवाई करेंगे।
- (ii) यद्यपि, परीक्षा के संचालन में अथवा मूल्यांकन की प्रक्रिया में गड़बड़ी के मुद्दों को लोकपाल को संदर्भित किया जा सकता है, तथापि, लोकपाल द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन अथवा अंको को पुनः योग करने हेतु कोई अपील अथवा आवेदन पर लोकपाल द्वारा सुनवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि भेदभाव की किसी विशिष्ट घटना के परिणामों को प्रभावित करने वाली किसी विशिष्ट अनियमितता को इंगित नहीं किया जाता है।
- (iii) लोकपाल, कथित रूप से किए गए भेदभाव की शिकायतों की सुनवाई करने के लिएन्याय मित्र के रूप में किसी भी व्यक्ति की सहायता प्राप्त कर सकता है।
- (iv) लोकपाल पीडितछात्र (छात्रों)से अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान करनेके लिए सभी प्रयास करेंगे।

8. लोकपाल तथा छात्र शिकायत निवारण समितियों द्वारा शिकायतों के निवारण हेतु प्रक्रिया

- (i) प्रत्येक संस्थान, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर एक ऑनलाइनपोर्टल तैयार करेगा, जहां कोई भी पीडितछात्र अपनी शिकायत के निवारण के लिए आवेदन कर सकता है।



- (ii) ऑनलाइन शिकायत प्राप्त होने पर संस्थान, ऑनलाइन शिकायत की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियों सहित शिकायत को उपर्युक्त छात्र शिकायत निवारण समिति को भेजेगा।
- (iii) छात्र शिकायत समिति, जैसा भी मामला हो, शिकायत की सुनवाई के लिए एक तिथि निर्धारित करेगी जिसकी जानकारी संस्थान और पीडितछात्र को दी जाएगी।
- (iv) पीडित छात्र या तो व्यक्तिगत रूप से पेश हो सकता है अथवा अपना पक्ष रखने के लिए अपने किसीप्रतिनिधि को अधिकृत कर सकता है।
- (v) छात्र शिकायत निवारण समिति द्वारा समाधान नहीं की गई शिकायतों को इन विनियमों में उपबंधित समयावधि के भीतर लोकपाल को भेजा जाएगा।
- (vi) संस्थान, शिकायतों के शीघ्र निपटान हेतुलोकपाल अथवा छात्र शिकायत निवारण समिति (समितियों), जैसा भी मामला हो, कासहयोग करेंगे।
- (vii) लोकपाल, संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, कार्यवाही के समापन पर, तत्संबंधी कारणों के साथ, इस प्रकार का आदेश पारित करेगा, जैसा कि शिकायत के निवारण के लिए उपयुक्त समझा जा सकता है और ऐसी राहत प्रदान कर सकता है जो पीडित छात्र के लिए उपयुक्त हो सकती है।
- (viii) संस्थान के साथ ही साथ पीडितछात्र को लोकपाल के हस्ताक्षर के तहत जारी की गई आदेश की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
- (ix) संस्थान, लोकपाल की सिफारिशों का अनुपालन करेगा।
- (x) जहां शिकायत झूठी या तुच्छ पाई जाती है उस स्थिति में लोकपाल शिकायतकर्ता के विरुद्ध उपर्युक्त कार्रवाई किए जाने की सिफारिश कर सकता है।

9. लोकपाल और छात्र शिकायत निवारण समितियों के संबंध में जानकारी:

संस्थान अपनी वेबसाइट और अपनी विवरणिका में स्पष्ट रूप से इसके क्षेत्राधिकार में आने वाली छात्र शिकायत निवारण समिति(समितियों) तथा अपील किए जाने के प्रयोजनार्थ लोकपाल के संबंध में सभी संगत जानकारियां उपलब्ध कराएगा।

10. अनुपालन नहीं किए जाने के परिणाम

आयोग, किसी भी संस्थान के संबंध में, जो जानबूझकर इन विनियमों का उल्लंघन करते हैं अथवा बार-बार लोकपाल या छात्र शिकायत निवारण समितियों की सिफारिश का पालन करने में विफल रहते हैं, जैसा भी मामला हो, जब तक संस्थान आयोग की संतुष्टि तक इन विनियमों का अनुपालन नहीं करता है, तब तक संस्थान के विरुद्ध निम्नवत् एक या एक से अधिक कार्यवाहियां की जा सकती हैं,

- क) अधिनियम की धारा 12बी के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्तता की घोषणा को वापस लेना;
- ख) संस्थान को आवंटित किसी अनुदान को रोका जा सकता है;
- ग) आयोग के किसी भी सामान्य अथवा विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत किसी भी सहायता को प्राप्त करने हेतु विचार किए जाने के लिए संस्थान को अयोग्य घोषित करना;
- घ) संस्थान को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए ऑनलाइन/मुक्त ओर दूरस्थ शिक्षा माध्यम से पाठ्यक्रम की पेशकश करने के लिए अयोग्य घोषित करना;
- ङ) ऑनलाइन/ मुक्त ओर दूरस्थ शिक्षा माध्यम से पाठ्यक्रमों की पेशकश करने की स्वीकृति को वापस लेना/रोकना/निलंबित करना;



- च) उपयुक्त मीडिया में प्रमुखता से प्रदर्शित कर और आयोग की वेबसाइट पर पोस्ट कर प्रवेश हेतु संभावित अभ्यर्थियों सहित जनसाधारण को सूचित करना तथा इस बाबत घोषणा करना कि संस्थान में शिकायतों के निवारण के लिए न्यूनतम मानक मौजूद नहीं हैं;
- छ) महाविद्यालय के मामले में, संबद्धता को वापस लेने के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय को सिफारिश करना;
- ज) सम विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में ऐसी कार्रवाई करना, जो आवश्यक, उचित एवं उपयुक्त हो;
- झ) सम विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषणा को वापस लिए जाने के लिए, यदि आवश्यक हो तो, केंद्र सरकार को सिफारिश करना;
- ञ) राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालय के मामले में राज्य सरकार को आवश्यक एवं उचित कार्रवाई करने की सिफारिश करना;
- ट) गैर अनुपालना के लिए संस्थान के प्रति ऐसी कार्रवाई करना जो आवश्यक एवं उपयुक्त समझी जाए।

बशर्ते इन विनियमों के अंतर्गत आयोग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि संस्थान को अपनी स्थिति को स्पष्ट करने एवं उसके पक्ष को सुने जाने का अवसर नहीं दिया गया हो।

11. इन विनियमों में उल्लिखित कोई भी शर्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायत निवारण) विनियम, 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त किसी पदधारी लोकपाल के कार्यकाल की अवधि के दौरान उसके पद पर बने रहने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी; कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् लोकपाल की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) के विनियम, 2023 के अनुरूप की जाएगी।

प्रा. मनिष र. जोशी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./13/2023-24]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2023

University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023

F.1-13/2022 (CPP-II).— In exercise of the powers conferred under clause (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in supersession of the University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2019, the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely -

1. SHORT TITLE, APPLICATION, AND COMMENCEMENT:

- (a) These regulations shall be called as the University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023.
- (b) They shall apply to all higher education institutions, whether established or incorporated by or under a Central Act or a State Act, and every institution recognized by the University Grants Commission under clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and to all institutions deemed to be a University declared as such under Section 3 therein and to all higher education institutions affiliated to a University.
- (c) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. OBJECTIVE

To provide opportunities for redressal of certain grievances of students already enrolled in any institution, as well as those seeking admission to such institutions, and a mechanism thereto.



3. DEFINITION:

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires-

- (a) "Act" means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- (b) "aggrieved student" means a student, who has any complaint in the matters relating to or connected with the grievances defined under these regulations.
- (c) "college" means any institution, so defined in clause (b) of sub-section (1) of section 12A of the Act.
- (d) "Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of the UGC Act, 1956.
- (e) "declared admission policy" means such policy, including the process there under, for admission to a course or program of study as may be offered by the institution by publication in the prospectus of the institution.
- (f) "grievance" means, and includes, complaint(s) made by an aggrieved student in respect of the following, namely:
- i. admission contrary to merit determined in accordance with the declared admission policy of the institution;
 - ii. irregularity in the process under the declared admission policy of the institution;
 - iii. refusal to admit in accordance with the declared admission policy of the institution;
 - iv. non-publication of a prospectus by the institution, in accordance with the provisions of these regulations;
 - v. publication by the institution of any information in the prospectus, which is false or misleading, and not based on facts;
 - vi. withholding of, or refusal to return, any document in the form of certificates of degree, diploma or any other award or other document deposited by a student for the purpose of seeking admission in such institution, with a view to induce or compel such student to pay any fee or fees in respect of any course or program of study which such student does not intend to pursue;
 - vii. demand of money in excess of that specified to be charged in the declared admission policy of the institution;
 - viii. violation, by the institution, of any law for the time being in force in regard to reservation of seats in admission to different category of students;
 - ix. non-payment or delay in payment of scholarships or financial aid admissible to any student under the declared admission policy of such institution, or under the conditions, if any, prescribed by the Commission;
 - x. delay by the institution in the conduct of examinations, or declaration of results, beyond the schedule specified in the academic calendar of the institution, or in such calendar prescribed by the Commission;
 - xi. failure by the institution to provide student amenities as set out in the prospectus, or is required to be extended by the institution under any provisions of law for the time being in force;
 - xii. non-transparent or unfair practices adopted by the institution for the evaluation of students;
 - xiii. delay in, or denial of, the refund of fees due to a student who withdraws admission within the time mentioned in the prospectus, subject to guidelines, if any, issued by the Commission, from time to time;
 - xiv. complaints of alleged discrimination of students from the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Women, Minorities or persons with disabilities categories;
 - xv. denial of quality education as promised at the time of admission or required to be provided;
 - xvi. harassment or victimization of a student, other than cases of harassment, which are to be proceeded against under the penal provisions of any law for the time being in force;
 - xvii. any action initiated/taken contrary to the statutes, ordinances, rules, regulations, or guidelines of the institution; and
 - xviii. any action initiated/taken contrary to the regulations and/or guidelines made/issued by the Commission and/or the regulatory body concerned.



- (g) "Institution" means a university as defined in sub-section (f) of Section 2 of the UGC Act, an institution declared as institution deemed to be university under Section 3 of the Act, and a college as defined under section 12A (1) (b) of the University Grants Commission Act, 1956.
- (h) "Ombudsperson" means the Ombudsperson appointed under these regulations;
- (i) "Prospectus" means and includes any publication, whether in print or otherwise, issued for providing fair and transparent information, relating to an institution, to the general public (including to those seeking admission in such institution) by such institution or any authority or person authorized by such institution to do so;
- (j) "Student" means a person enrolled, or seeking admission to be enrolled, in any institution, to which these regulations apply, through any mode i.e., Formal / Open and Distance Learning (ODL) / Online;
- (k) "Students' Grievance Redressal Committee (SGRC)" means a committee constituted under these regulations, at the level of an institution; and
- (l) "University" means a University so defined in clause (f) of section 2 of the Act or, where the context may be, an institution deemed to be University declared as such under Section 3 thereof.
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the University Grants Commission Act, 1956 shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

4. MANDATORY PUBLICATION OF PROSPECTUS, ITS CONTENTS, AND PRICING:

- (1) Every institution, shall publish and/or upload on its website, before expiry of at least sixty days prior to the date of the commencement of the admission to any of its courses or programs of study, a prospectus containing the following for the information of persons intending to seek admission to such institution and the general public, namely:
- (a) the list of programs of study and courses offered along with the broad outlines of the syllabus specified by the appropriate statutory authority or by the institution, as the case may be, for every course or program of study, including teaching hours, practical sessions and other assignments;
- (b) the number of seats approved by the appropriate statutory authority in respect of each course or program of study for the academic year for which admission is proposed to be made;
- (c) the conditions of educational qualifications and eligibility including the minimum and maximum age limit of persons for admission as a student in a particular course or program of study, specified by the institution;
- (d) the process of selection of eligible candidates applying for such admission, including all relevant information in regard to the details of test or examination for selecting such candidates for admission to each course or program of study and the amount of fee prescribed for the admission test;
- (e) each component of the fee, deposits and other charges payable by the students admitted to such institution for pursuing a course or program of study, and the other terms and conditions of such payment;
- (f) rules/regulations for imposition and collection of any fines in specified heads or categories, minimum and maximum fines may be imposed;
- (g) the percentage of tuition fee and other charges refundable to a student admitted in such institution in case such student withdraws from such institution before or after completion of course or program of study and the time within and the manner in which such refund shall be made to that student;
- (h) details of the teaching faculty, including their educational qualifications, along with their type of appointment (Regular/visiting/guest) and teaching experience of every member thereof;
- (i) information with regard to physical and academic infrastructure and other facilities including hostel accommodation and its fee, library, hospital, or industry wherein the practical training is to be imparted to the students and in particular the amenities accessible by students on being admitted to the institution;
- (j) all relevant instructions in regard to maintaining the discipline by students within or outside the campus of the institution, and, in particular such discipline relating to the prohibition of ragging of any student or students and the consequences thereof and for violating the provisions of any regulation in this behalf made by the relevant statutory regulatory authority; and
- (k) Any other information as may be specified by the Commission.

Provided that an institution shall publish/upload information referred to in clauses (a) to (k) of this regulation, on its website, and the attention of prospective students and the general public shall be drawn to such publication being on the website through advertisements displayed prominently indifferent newspapers and through other media.



- (2) Every institution shall fix the price of each printed copy of the prospectus, being not more than the reasonable cost of its publication and distribution and no profit be made out of the publication, distribution, or sale of prospectus.

5. STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES (SGRC):

- (i) A complaint from an aggrieved student relating to the institution shall be addressed to the Chairperson, Students' Grievance Redressal Committee (SGRC).
- (ii) Every Institution shall constitute such number of Students' Grievance Redressal Committees (SGRC), as may be required to consider grievances of the students, with the following composition, namely:
 - a) A Professor - Chairperson
 - b) Four Professors/Senior Faculty Members of the Institution as Members.
 - c) A representative from among students to be nominated on academic merit/excellence in sports/performance in co-curricular activities-Special Invitee.
- (iii) Atleast one member or the Chairperson shall be a woman and atleast one member or the Chairperson shall be from SC/ST/OBC category.
- (iv) The term of the chairperson and members shall be for a period of two years.
- (v) The term of the special invitee shall be one year.
- (vi) The quorum for the meeting including the Chairperson, but excluding the special invitee, shall be three.
- (vii) In considering the grievances before it, the SGRC shall follow principles of natural justice.
- (viii) The SGRC shall send its report with recommendations, if any, to the competent authority of the institution concerned and a copy thereof to the aggrieved student, preferably within a period of 15 working days from the date of receipt of the complaint.
- (ix) Any student aggrieved by the decision of the Students' Grievance Redressal Committee may prefer an appeal to the Ombudsperson, within a period of fifteen days from the date of receipt of such decision.

6. APPOINTMENT, TENURE, REMOVAL AND CONDITIONS OF SERVICES OF OMBUDSPERSON:

- (i) Each University shall appoint Ombudsperson for redressal of grievances of students of the university and colleges/institutions affiliated with the university under these regulations.
- (ii) There shall be one or more part-time functionaries designated as Ombudspersons to hear, and decide on, appeals preferred against the decisions of the SGRCs.
- (iii) The Ombudsperson shall be a retired Vice-Chancellor or a retired Professor (who has worked as Dean/HOD) and has 10 years' experience as a Professor at State/Central Universities/Institutions of National Importance/Deemed to be Universities or a former District Judge.
- (iv) The Ombudsperson shall not, at the time of appointment, during one year before appointment, or in the course of his/her tenure as Ombudsperson, be in conflict of interest with the Institution where his/her personal relationship, professional affiliations or financial interest may compromise or reasonably appear to compromise, the independence of judgment towards the Institution.
- (v) The Ombudsperson shall be appointed for a period of three years or until he/she attains the age of 70 years, whichever is earlier, from the date of assuming office, and shall be eligible for reappointment for another one term.
- (vi) For conducting the hearings, the Ombudsperson shall be paid a sitting fee, per diem, in accordance with the norms fixed by the respective university and shall, in addition, be eligible for reimbursement of the expenditure incurred on conveyance.
- (vii) The University may remove the Ombudsperson from office, on charges of proven misconduct or misbehaviour.
- (viii) No order of removal of Ombudsperson shall be made except after an inquiry made in this regard by a person, not below the rank of a retired judge of the High Court in which a reasonable opportunity of being heard is given to the Ombudsperson.

7. FUNCTIONS OF OMBUDSPERSON:

- (i) The Ombudsperson shall hear appeals from an aggrieved student, only after the student has availed all other remedies provided under these regulations.



- (ii) While issues of malpractices in the conduct of examination or in the process of evaluation may be referred to the Ombudsperson, no appeal or application for revaluation or re-totalling of answer sheets from an examination, shall be entertained by the Ombudsperson unless specific irregularity materially affecting the outcome or specific instance of discrimination is indicated.
- (iii) The Ombudsperson may avail assistance of any person, as amicus curiae, for hearing complaints of alleged discrimination.
- (iv) The Ombudsperson shall make all efforts to resolve the grievances within a period of 30 days of receiving the appeal from the aggrieved student(s).

8. PROCEDURE FOR REDRESSAL OF GRIEVANCES BY OMBUDSPERSONS AND STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES:

- (i) Each institution shall, within a period of three months from the date of issue of this notification, have an online portal where any aggrieved student may submit an application seeking redressal of grievance.
- (ii) On receipt of an online complaint, the institution shall refer the complaint to the appropriate Students' Grievance Redressal Committee, along with its comments within 15 days of receipt of complaint on the online portal.
- (iii) The Students' Grievance Redressal Committee, as the case may be, shall fix a date for hearing the complaint which shall be communicated to the institution and the aggrieved student.
- (iv) An aggrieved student may appear either in person or authorize a representative to present the case.
- (v) Grievances not resolved by the Students' Grievance Redressal Committee within the time period provided in these regulations may be referred to the Ombudsperson by the university.
- (vi) Institutions shall extend co-operation to the Ombudsperson or the Student Grievance Redressal Committee(s), in early redressal of grievances.
- (vii) The Ombudsperson shall, after giving reasonable opportunities of being heard to the parties concerned, on the conclusion of proceedings, pass such order, with reasons thereof, as may be deemed fit to redress the grievance and provide such relief as may be appropriate to the aggrieved student.
- (viii) The institution, as well as the aggrieved student, shall be provided with copies of the order under the signature of the Ombudsperson.
- (ix) The institution shall comply with the recommendations of the Ombudsperson.
- (x) The Ombudsperson may recommend appropriate action against the complainant, where a complaint is found to be false or frivolous.

9. INFORMATION REGARDING OMBUDSPERSONS AND STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES:

An institution shall furnish, prominently, on its website and in its prospectus, all relevant information in respect of the Students' Grievance Redressal Committee(s) coming in its purview, and the Ombudsperson for the purpose of appeals.

10. CONSEQUENCES OF NON-COMPLIANCE:

The Commission shall in respect of any institution, which wilfully contravenes these regulations or repeatedly fails to comply with the recommendation of the Ombudsperson or the Students' Grievance Redressal Committee, as the case may be, proceed to take one or more of the following actions till the institution complies with these Regulations to the satisfaction of the Commission, namely:

- (a) withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the Act;
- (b) withholding any grant allocated to the Institution;



- (c) declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programs of the Commission;
- (d) declaring the institution ineligible to offer courses through Online/ODL mode for a specified period;
- (e) withdrawing / withholding / suspending the approval for offering courses through Online/ODL mode;
- (f) informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed prominently in suitable media and posted on the website of the Commission, declaring that the institution does not possess the minimum standards for redressal of grievances;
- (g) recommend to the affiliating University for withdrawal of affiliation, in case of a college;
- (h) take such action as it may deem necessary, appropriate and fit, in case of an institution deemed to be University;
- (i) recommend to the Central Government, if required, for withdrawal of declaration as institution deemed to be a University, in case of an institution deemed to be University;
- (j) recommend to the State Government to take necessary and appropriate action, in case of a University established or incorporated under a State Act;
- (k) such other action as may be deemed necessary and appropriate against an institution for non-compliance.

Provided that no action shall be taken by the Commission under this regulation, unless the institution has been provided an opportunity of being heard to explain its position.

11. Nothing mentioned herein above in these regulations shall affect the continuance in office, during the currency of the term, of an incumbent Ombudsperson appointed under the provisions of the UGC (Redress of Grievances of Students) Regulations, 2019; where after, the appointment of Ombudsperson shall be made as per University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023.

Prof. MANISH R. JOSHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./13/2023-24]





ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो. रजनीश जैन
सचिव

Prof. Rajnish Jain
Secretary



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: 011-23236288/23239337

Fax : 011-2323 8858

E-mail : secy.ugc@nic.in

D. O. No. F. 1-15/2009 (ARC) pt.III

16 SEP 2022 September, 2022

Dear Madam/Sir,

In pursuance to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 08.05.2009 in Civil Appeal No. 887/2009, in exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the UGC notified "Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009". The Regulations are available on the UGC website i.e. www.ugc.ac.in & www.antiragging.in.

It is once again brought to your kind notice that ragging is a criminal offence and UGC has framed regulations on curbing the menace of ragging in higher educational institutions in order to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging. These regulations are mandatory and all institutions are required to take necessary steps for its implementation in toto including the monitoring mechanism. Any violation of these regulations will be viewed seriously. If any institution fails to take adequate steps to prevent ragging or does not act in accordance with these Regulations or fails to punish perpetrators of incidents of ragging suitably, it will attract punitive action against itself by the UGC.

You are requested to step up anti-ragging mechanism by way of adequate publicity through various mediums; constitution of Anti-Ragging committee and Anti-Ragging squad, setting up of Anti-Ragging Cell, installing CCTV cameras at vital points, Anti-Ragging workshops and seminar, updating all websites with nodal officers' complete details, alarm bells etc. Regular interaction and counseling with the students, identification of trouble-triggers and mention of Anti-Ragging warning in the institution's E-prospectus and E-information booklets/brochures must be ensured. Surprise inspection of hostels, students' accommodation, canteens, rest cum recreational rooms, toilets, bus-stands must be carried out & Anti-Ragging posters must be displayed at all prominent places like Admission Centre, Departments, Library, Canteen, Hostel, Common facilities etc. These posters are available on UGC website www.ugc.ac.in. The size of posters should be 8x6 feet. Any other measure which would augur well in preventing/quelling ragging and any uncalled for behaviour/incident must be undertaken.

Students in distress due to ragging related incidents can call the National Anti-Ragging Helpline 1800-180-5522 (24x7 Toll Free) or e-mail the Anti-Ragging Helpline at helpline@antiragging.in. For any other information regarding ragging you may please visit the UGC website i.e. www.ugc.ac.in & www.antiragging.in and contact UGC monitoring agency i.e. Centre for Youth (C4Y) on Mobile No. 09818044577 (only in case of emergency).

UGC also drives an Anti-Ragging Media Campaign through different modes and has undertaken the following activities to promote the campaign which are available on UGC website i.e. www.ugc.ac.in

- UGC developed 05 TVCs of 30 seconds each with different perspective i.e. Parents, Victim and Offenders.
- UGC designed and distributed 04 types of posters amongst Universities / Regulatory Authorities / Councils / IITs / NITs / other educational institutions for their prominent display.
- UGC consecutively organized 02 Anti-Ragging Competitions for students/faculty/general public for the wider awareness of the menace of ragging.

Mr. Sandesh
Chhang
17/9/22





ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो. रजनीश जैन
सचिव
Prof. Rajnish Jain
Secretary



सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: 011-23236288/23239337

Fax : 011-2323 8858

E-mail : secy.ugc@nic.in

सितंबर, 2022

16 SEP 2022

ब०श०मि.स० 1-15/2009 (एआरसी) पीटी.।।।

प्रिय महोदया / महोदय,

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 887/2009 दिनांक 8.5.2009 से प्राप्त निर्देशों तथा भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग-निषेध तथा रैगिंग रोकने के संकल्प को ध्यान में रखते हुए यू.जी.सी. के अधिनियम 1956 धारा 26 उपखंड (G) उपखंड (1) के अधिकारों का प्रयोग करते हुए, यू.जी.सी. ने "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009" को अधिसूचित किया है। संपूर्ण जानकारी के लिये यह अधिनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट: www.ugc.ac.in और www.antiragging.in पर उपलब्ध है। यू.जी.सी. द्वारा अधिसूचित किया गया यह अधिनियम सभी शिक्षण संस्थानों के लिये अनिवार्य है और सभी संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसे पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए निगरानी प्रक्रिया सहित अन्य आवश्यक कदम उठावेंगे और इस अधिनियम में उल्लेखित भागों के किसी भी तरह के उल्लंघन को उनके द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। यदि कोई संस्थान रैगिंग को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहता है या यू.जी.सी. द्वारा अधिसूचित अधिनियम के अनुसार कार्रवाई नहीं करता है और रैगिंग की घटनाओं के दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने में विफल रहता है तो यूजीसी द्वारा उस संस्थान के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी।

इस संदर्भ में सभी संस्थानों से अनुरोध है कि विभिन्न रैगिंग-रोधी माध्यमों के पर्याप्त प्रचार प्रसार, रैगिंग-रोधी समिति एवं रैगिंग-रोधी दस्ते का गठन, रैगिंग-रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना, महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर, रैगिंग-रोधी कार्यशालाएं और सेमिनार का आयोजन, सभी वेबसाइटों को नोडल अधिकारियों के पूर्ण विवरण सहित अपडेट कर, अलार्म घंटी आदि द्वारा रैगिंग-रोधी तंत्र को आगे बढ़ाएं छात्रों से नियमित बातचीत और काउंसलिंग, शरारती छात्रों की पहचान और संस्थान के ई-प्रोस्पेक्टस और ई-सूचना पुस्तिकाओं / विवरणिकाओं में रैगिंग-रोधी चेतावनी का उल्लेख सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, हॉस्टल, छात्रावास, जल पान गृह, विद्यालय व मनोरंजन कक्ष, शौचालयों व बस अड्डों का औचक निरीक्षण किया जाए तथा संस्थान का प्रवेश केंद्र, विभागों, पुस्तकालयों, जल पान गृह, हॉस्टल, सार्वजनिक सुविधाएँ आदि जैसे सभी प्रमुख स्थानों पर रैगिंग-रोधी पोस्टर लगाये जाएं। ये पोस्टर यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है। पोस्टरों का आकार 8 x 6 फीट होना चाहिए। संस्थान रैगिंग व किसी अनुचित व्यवहार / घटना की रोकथाम के लिये कोई अन्य उचित उपाय भी कर सकते हैं।

रैगिंग से जुड़ी घटनाओं के कारण संकट में पड़े छात्र राष्ट्रीय रैगिंग-रोधी हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5522 (24x7 टोलफ्री) पर कॉल कर सकते हैं या रैगिंग-रोधी helpline@antiragging.in पर ई-मेल कर सकते हैं। रैगिंग संबंधित अन्य जानकारी के लिये कृपया यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in और www.antiragging.in पर जाएँ और यूजीसी की निगरानी एजेंसी अर्थात् सेंटर फॉर यूथ (सी4वाई) के मोबाइल नंबर 09818044577 पर संपर्क करें (केवल आपातकाल के मामले में)।

यूजीसी विभिन्न प्रकार के रैगिंग - रोधी मीडिया अभियान भी चलाती है और यूजीसी ने रैगिंग निषेध को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की हैं जो यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं:-

- क) यूजीसी ने माता-पिता, पीड़ित और दोषियों के परिप्रेक्ष्य में पांच टीवी क्लिप (प्रत्येक 30 सेकंड) तैयार की हैं।
- ख) यूजीसी ने चार प्रकार के पोस्टर तैयार किये हैं और इनको विश्वविद्यालयों/नियामक प्राधिकरणों / परिषदों / आईआईटी / एनआईटी / अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रमुख रूप से प्रदर्शित करने के लिए आबंटित किया है।



2/9/22

In compliance of the 2nd Amendment in UGC Regulations, you are requested to make it compulsory for each student and every parent to submit an online undertaking every academic year at www.antiragging.in

You are also requested to implement the revised procedure for students to file online Anti-Ragging affidavit. The student will receive an e-mail with his/her registration number. The student will forward that e-mail to the Nodal officer in his/her university/college e-mail. **(Please note that the student will not receive pdf affidavits and he/she is not required to print & sign it as it used to be in the earlier case).**

Universities/Colleges have to display the email address and contact number of the Nodal Officer of Anti-Ragging Committee of their university/college on their website and campus areas like Admission Centre, Departments, Library, Canteen, Hostel, and Common facilities, etc.

Universities and Colleges are requested to insert a mandatory column in their university/colleges admission form as per the given format:

Anti Ragging Undertaking Reference no:	<input type="text"/>
--	----------------------

Universities are also requested to fill online compliance on www.antiragging.in and also immediately instruct all the colleges under their purview to follow it.

With kind regards,


Yours sincerely,


(Rajnish Jain)

The Vice-Chancellor of all Universities

Copy to:

1. All Regulatory Authorities (As per list attached) with a request to take necessary steps to ensure these activities in all the Universities/Institutions under your ambit.
2. UGC, Regional Offices (As per list attached) with a request to take necessary steps to ensure these activities in all the Colleges/Institutions under your ambit.
3. Ms. Jasleen Kaur, Under Secretary (HE), Department of Higher Education, Ministry of Education, Room No. 221, 'C' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001 (jasleen.kaur@nic.in).
4. Deputy Secretary, (website), UGC (for uploading on UGC website & under ragging related circulars).
5. Ms. Alka Tomar, Centre for Youth (C4Y) (alka.tomar@c4yindia.org) (for uploading on antiragging.in)


(Dr. Archana Thakur)
Joint Secretary



ग) यूजीसी ने छात्रों/ शिक्षकों/ आम जनता के बीच व्यापक जागरूकता लाने के लिये रैगिंग-रोधी विषय से संबंधित दो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है।

यूजीसी विनियमों के दूसरे संशोधन के अनुपालन में, आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक छात्र और प्रत्येक माता-पिता द्वारा www.antiragging.in पर प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में एक ऑनलाइन बचनबंध (Undertaking) जमा करना अनिवार्य बनाएं।

आपसे यह भी अनुरोध है कि छात्रों द्वारा ऑनलाइन रैगिंग-रोधी शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए संशोधित प्रक्रिया को लागू करें। छात्रों को उसकी पंजीकरण संख्या के साथ एक ई-मेल प्राप्त होगा। छात्र उस ई-मेल को अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के नोडल अधिकारी के ई-मेल में अग्रेषित करेगा। (कृपया ध्यान दें कि छात्रों को पीडीएफ शपथ-पत्र प्राप्त नहीं होगा और उन्हें इसे प्रिंट कर हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि पहले के मामले में हुआ करता था)।

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की रैगिंग रोधी समिति के नोडल अधिकारी का ई-मेल, पता और संपर्क नंबर अपनी वेबसाइट और परिसर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे प्रवेश केंद्र, विभागों, पुस्तकालय, कैटीन, छात्रावास और सामान्य सुविधा आदि स्थानों पर प्रदर्शित करना होगा।

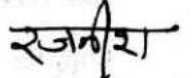
विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अनुरोध है कि वे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों के प्रवेश पत्र में निम्नवत एक अनिवार्य कॉलम डालें:

रैगिंग रोधी बचन पत्र संदर्भ संख्या:

विश्वविद्यालयों से यह भी अनुरोध है कि वे ऑनलाइन अनुपालन www.antiragging.in पर भरें और अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी महाविद्यालयों को भी इसका पालन करने का निर्देश दें।

सादर,

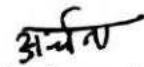
भवदीय,


(रजनीश जैन)

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति

प्रतिलिपि:

1. सभी नियामक प्राधिकरणों (संलग्न सूची के अनुसार) से अनुरोध किया जाता है कि आप अपने परिधि क्षेत्र में आने वाले सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में इन गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय (संलग्न सूची के अनुसार) से अनुरोध किया जाता है कि आप अपने परिधि क्षेत्र में आने वाले सभी महाविद्यालयों/संस्थानों में इन गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
3. सुश्री जसलीन कौर, अवर सचिव (एचई), उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली-110001(jasleen.kaur@nic.in)।
4. उप सचिव, (वेबसाइट), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी की वेबसाइट पर रैगिंग से संबंधित परिपत्रों को अपलोड करने के लिए)।
5. सुश्री अलका तोमर, सेंटर फॉर यूथ (C4Y) (alka.tomar@c4yindia.org) (antiragging.in पर अपलोड करने के लिए)।


(डॉ अर्चना ठाकुर)
संयुक्त सचिव





ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो. रजनीश जैन
सचिव

Prof. Rajnish Jain
Secretary



सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph : 011-23236288/23239337

Fax : 011-2323 8858

E-mail : secy.ugc@nic.in

D. O. No. F. 3-2/2021 (ARC)

27 OCT 2021 October, 2021

'SPEED POST'

Subject: Revised procedure for students to file online Anti Ragging Affidavit.

Dear Madam/Sir,

As you are aware, in pursuance to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 8.5.2009 in Civil Appeal No. 887/2009, the UGC notified "Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009" and in compliance of the 2nd Amendment in UGC Regulations, it is compulsory for each student and his/her parent/Guardian to submit an online undertaking each academic year at either of the two designated web sites, namely, **www.antiragging.in** and **www.amanmovement.org**.

As part of UGC's initiative towards reduction of compliance burden of its stakeholders, UGC has revised the procedure for students to file online Anti Ragging Affidavit.

The revised procedure is as follows:

Step 1: A student will submit his/her details on the same web sites (**www.antiragging.in** and **www.amanmovement.org**) as before; read and confirm that he/she and his/her parents/Guardians have read and understood the regulations on curbing the menace of ragging. He/She will confirm & agree that he/she will not engage in ragging in any form. (Step 1 is the same like before).

Step 2: The student will receive an E MAIL with his/her registration number and a web link. The student will forward the link to the E mail of the Nodal officer in his/her university/college. **(Please note that the student will not receive pdf affidavits and he/she is not required to print & sign it as used to be the case earlier).**

Step 3: The Nodal Officer in the university/college can click on the link of any forwarded e mails that he/she will receive from any student of his/her college to get the list of those students who have submitted Anti Ragging Affidavits/Undertakings in his/her college. The list will be updated every 24 hours.

Contd.../-



-02-

Universities and Colleges are requested to insert a **mandatory column** in your university/colleges admission form as per the given format:

Anti Ragging Undertaking Reference no:	<input type="text"/>
--	----------------------

You are also requested to display the email address and contact number of the Nodal Officer of Anti Ragging of your university/college in your website and campus areas like Admission Centre, Departments, Library, Canteen, Hostel, and Common facilities etc. to create awareness about the revised procedure for students to file online Anti Ragging Affidavit.

In addition to this, you are also requested to create E-admission booklet or brochure, E-leaflets giving details on guidance in case of ragging to admitted students instead of print/hard copy.

With kind regards,

Yours sincerely,


(Rajnish Jain)

The Vice-Chancellor of all Universities

The Principal of all Colleges


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 29, 2016/आषाढ़ 8, 1938

No. 269]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 29, 2016/ASHADHA 8, 1938

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2016

सं. फा. 1-15/2009(ए.आर.सी.).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (3 का 1956) के अनुच्छेद 26 के उप-अनुच्छेद (1) की धारा (जी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्न विनियमों का सृजन करता है :—

- (1) ये विनियम "उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग अपराध निषेध विनियम, 2016 (तृतीय संशोधन)" के नाम से जाने जाएं।
- (2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू माने जाएं।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, "उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग अपराध निषेध, 2009" (इसके उपरान्त प्रमुख विनियमों के सन्दर्भ में) के पैरा 3 के उप शीर्षक "रैगिंग कैसे होती है" 3(झ) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाए :—
 - 3(ञ). किसी भी छात्र को (नवीन प्रविष्ट या अन्यथा) लक्षित करके रंग, प्रजाति, धर्म, जाति, जातिमूल, लिंग (उभय लैंगिकों सहित) लैंगिक प्रवृत्ति, बाह्य स्वरूप, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीयमूल, भाषा वैशिष्ट्य, जन्म, निवास स्थान या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर शारीरिक अथवा मानसिक प्रताड़ना (दबंगई एवं बहिष्करण) का कृत्य।

प्रोफेसर जसपाल एस. सन्धू, सचिव (यूजीसी)

[विज्ञापन III/4/असा./149/(113)]



UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2016

No. F. 1-15-/2009 (ARC).—In exercise of powers conferred under clause (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following regulations namely:—

- (1) These regulations may be called “Curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions (third amendment), Regulations, 2016.”
 - (2) They shall come into force on the date of their publications in the Official Gazette.
2. In UGC Regulations on Curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009 (herein-after referred to as the Principal regulations), in Para 3 the following shall be added after 3(i) under heading what constitutes Ragging.—
- 3(j). Any act of physical or mental abuse (including bullying and exclusion) targeted at another student (fresher or otherwise) on the ground of colour, race, religion, caste, ethnicity, gender (including transgender), sexual orientation, appearance, nationality, regional origins, linguistic identity, place of birth, place of residence or economic background.

Prof. JASPAL S. SANDHU, Secy. (UGC)

[ADVT. III/4/Exty./149/(113)]



DRAFT

**UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI - 110 002**

NO. F 1-16/2007 (CPP-II)

April, 2009

**UGC REGULATION ON CURBING THE MENACE OF RAGGING IN HIGHER
EDUCATIONAL INSTITUTIONS, 2009**

In exercise of the powers conferred by Clause (g) of Sub-Section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission hereby makes the following Regulations, namely -

1. Title, commencement and applicability:-

- 1.1. These regulations shall be called the "UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009".
- 1.2. They shall come into force with immediate effect.
- 1.3. They shall apply to all the universities established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, to all institutions deemed to be university under Section 3 of the UGC Act, 1956, to all other higher educational institutions, including the departments, constituent units and all the premises (academic, residential, sports, canteen, etc) of such universities, deemed universities and other higher educational institutions, whether located within the campus or outside, and to all means of transportation of students whether public or private.

2. Objective:-

To root out ragging in all its forms from universities, colleges and other educational institutions in the country by prohibiting it by law, preventing its occurrence by following the provisions of these Regulations and punishing those who indulge in ragging as provided for in these Regulations and the appropriate law in force.

3. Definitions:- For the purposes of these Regulations:-

- 3.1. "college" means any institution, whether known as such or by any other name, which provides for a programme of study beyond 12 years of schooling for obtaining qualification from a university and which, in accordance with the rules and regulations of such university, is recognized as competent to provide for such programme of study and present students undergoing such programme of study for the examination for the award of such qualification.



- 3.2. "Head of the institution" means the 'Vice-Chancellor' in case of a university/deemed to be university, 'Principal' in case of a college, 'Director' in case of an institute.
- 3.3. "institution" means a higher educational institution (HEI), like a university, a college, an institute, etc. imparting higher education beyond 12 years of schooling leading to a degree (graduate, postgraduate and/or higher level) and/or to a university diploma.
- 3.4. "Ragging" means the following:
Any conduct whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness any other student, indulging in rowdy or undisciplined activities which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in a fresher or a junior student or asking the students to do any act or perform something which such student will not in the ordinary course and which has the effect of causing or generating a sense of shame or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of a fresher or a junior student.
- 3.5. "Statutory/Regulatory body" means a body so constituted by a Central/ State Government legislation for setting and maintaining standards in the relevant areas of higher education, such as the All India Council for Technical Education (AICTE), the Bar Council of India (BCI), the Dental Council of India (DCI), the Distance Education Council (DEC), the Indian Council of Agricultural Research (ICAR), the Indian Nursing Council (INC), the Medical Council of India (MCI), the National Council for Teacher Education (NCTE), the Pharmacy Council of India (PCI), etc. and the State Higher Education Councils.
- 3.6. "University" means a university established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, an institution deemed to be university under Section 3 of the UGC Act, 1956, or an institution specially empowered by an Act of Parliament to confer or grant degrees.

4. Punishable ingredients of Ragging:-

- Abetment to ragging;
- Criminal conspiracy to rag;
- Unlawful assembly and rioting while ragging;
- Public nuisance created during ragging;
- Violation of decency and morals through ragging;
- Injury to body, causing hurt or grievous hurt;
- Wrongful restraint;
- Wrongful confinement;
- Use of criminal force;
- Assault as well as sexual offences or unnatural offences;
- Extortion;
- Criminal trespass;
- Offences against property;
- Criminal intimidation;



- Attempts to commit any or all of the above mentioned offences against the victim(s);
- Physical or psychological humiliation;
- All other offences following from the definition of "Ragging".

5. Measures for prohibition of ragging at the institution level:-

- 5.1 The institution shall strictly observe the provisions of the Act of the Central Government and the State Governments, if any, or if enacted, considering ragging as a cognizable offence under the law on a par with rape and other atrocities against women and ill-treatment of persons belonging to the SC/ST, and prohibiting ragging in all its forms in all institutions.
- 5.2 Ragging in all its forms shall be totally banned in the entire institution, including its departments, constituent units, all its premises (academic, residential, sports, canteen, etc) whether located within the campus or outside and in all means of transportation of students whether public or private.
- 5.3 The institution shall take strict action against those found guilty of ragging and/or of abetting ragging.

6 Measures for prevention of ragging at the institution level:-

6.1 Before admissions:-

- 6.1.1 The advertisement for admissions shall clearly mention that ragging is totally banned in the institution, and anyone found guilty of ragging and/or abetting ragging is liable to be punished appropriately (for punishments, ref. section 8 below).
- 6.1.2 The brochure of admission/instruction booklet for candidates shall print in block letters these Regulations in full (including Annexures).
- 6.1.3 The 'Prospectus' and other admission related documents shall incorporate all directions of the Supreme Court and /or the Central or State Governments as applicable, so that the candidates and their parents/ guardians are sensitized in respect of the prohibition and consequences of ragging. If the institution is an affiliating university, it shall make it mandatory for the institutions under it to compulsorily incorporate such information in their 'Prospectus'.
- 6.1.4 The application form for admission/ enrolment shall have a printed undertaking, preferably both in English/Hindi and in one of the regional languages known to the institution and the applicant (English version given in Annexure I, Part I), to be filled up and signed by the candidate to the effect that he/she is aware of the law regarding prohibition of ragging as well as the punishments, and to the effect that he/she has not been expelled and/or debarred from admission by any institution and that he/she, if found guilty of the offence of ragging and/or abetting ragging, is liable to be punished appropriately.



- 6.1.5 The application form shall also contain a printed undertaking, preferably both in English/Hindi and in one of the regional languages known to the institution and the parent/ guardian (English version given in Annexure I, Part II), to be signed by the parent/ guardian of the applicant to the effect that he/ she is also aware of the law in this regard and agrees to abide by the punishment meted out to his/ her ward in case the latter is found guilty of ragging and/or abetting ragging.
- 6.1.6 The application for admission shall be accompanied by a document in the form of the School Leaving Certificate/Transfer Certificate/ Migration Certificate/ Character Certificate which shall include a report on the behavioral pattern of the applicant, so that the institution can thereafter keep intense watch upon a student who has a negative entry in this regard.
- 6.1.7 A student seeking admission to the hostel shall have to submit additional undertaking in the form of Annexure I (both Parts) along with his/ her application for hostel accommodation.
- 6.1.8 At the commencement of the academic session the Head of the Institution shall convene and address a meeting of various functionaries/agencies, like Hostel Wardens, representatives of students, parents/ guardians, faculty, district administration including police, to discuss the measures to be taken to prevent ragging in the Institution and steps to be taken to identify the offenders and punish them suitably.
- 6.1.9 To make the community at large and the students in particular aware of the dehumanizing effect of ragging, and the approach of the institution towards those indulging in ragging, big posters (preferably multicolored with different colours for the provisions of law, punishments, etc.) shall be prominently displayed on all Notice Boards of all departments, hostels and other buildings as well as at vulnerable places. Some of such posters shall be of permanent nature in certain vulnerable places.
- 6.1.10 The institution shall request the media to give adequate publicity to the law prohibiting ragging and the negative aspects of ragging and the institution's resolve to ban ragging and punish those found guilty without fear or favour.
- 6.1.11 The institution shall identify, properly illuminate and man all vulnerable locations.
- 6.1.12 The institution shall tighten security in its premises, especially at the vulnerable places. If necessary, intense policing shall be resorted to at such points at odd hours during the early months of the academic session.
- 6.1.13 The institution shall utilize the vacation period before the start of the new academic year to launch wide publicity campaign against ragging through posters, leaflets, seminars, street plays, etc.
- 6.1.14 The faculties/ departments/ units of the institution shall have induction arrangements (including those which anticipate, identify



and plan to meet any special needs of any specific section of students) in place well in advance of the beginning of the academic year with a clear sense of the main aims and objectives of the induction process.

6.2 On admission:-

- 6.2.1 Every fresh student admitted to the institution shall be given a printed leaflet detailing when and to whom he/she has to turn to for help and guidance for various purposes (including Wardens, Head of the institution, members of the anti-ragging committees, relevant district and police authorities), addresses and telephone numbers of such persons/authorities, etc., so that the fresher need not look up to the seniors for help in such matters and get indebted to them and start doing things, right or wrong, at their behest. Such a step will reduce the freshers' dependence on their seniors.
- 6.2.2 The institution through the leaflet mentioned above shall explain to the new entrants the arrangements for their induction and orientation which promote efficient and effective means of integrating them fully as students.
- 6.2.3 The leaflet mentioned above shall also inform the freshers about their rights as bona fide students of the institution and clearly instructing them that they should desist from doing anything against their will even if ordered by the seniors, and that they have nothing to fear as the institution cares for them and shall not tolerate any atrocities against them.
- 6.2.4 The leaflet mentioned above shall contain a calendar of events and activities laid down by the institution to facilitate and complement familiarization of freshers with the academic environment of the institution.
- 6.2.5 The institution shall also organize joint sensitization programmes of 'freshers' and seniors.
- 6.2.6 Freshers shall be encouraged to report incidents of ragging, either as victims, or even as witnesses.

6.3 At the end of the academic year:-

- 6.3.1 At the end of every academic year the Vice-Chancellor/ Dean of Students Welfare/ Director/ Principal shall send a letter to the parents/ guardians of the students who are completing the first year informing them about the law regarding ragging and the punishments, and appealing to them to impress upon their wards to desist from indulging in ragging when they come back at the beginning of the next academic session.
- 6.3.2 At the end of every academic year the institution shall form a 'Mentoring Cell' consisting of Mentors for the succeeding academic year. There shall be as many levels or tiers of Mentors as



the number of batches in the institution, at the rate of 1 Mentor for 6 freshers and 1 Mentor of a higher level for 6 Mentors of the lower level.

6.4 Setting up of Committees and their functions:-

- 6.4.1 The Anti-Ragging Committee:- The Anti-Ragging Committee shall be headed by the Head of the institution and shall consist of representatives of faculty members, parents, students belonging to the freshers' category as well as seniors and non-teaching staff. It shall monitor the anti-ragging activities in the institution, consider the recommendations of the Anti-Ragging Squad and take appropriate decisions, including spelling out suitable punishments to those found guilty.
- 6.4.2 The Anti-Ragging Squad:- The Anti-Ragging Squad shall be nominated by the Head of the institution with such representation as considered necessary and shall consist of members belonging to the various sections of the campus community. The Squad shall have vigil, oversight and patrolling functions. It shall be kept mobile, alert and active at all times and shall be empowered to inspect places of potential ragging and make surprise raids on hostels and other hot spots. The Squad shall investigate incidents of ragging and make recommendations to the Anti-Ragging Committee and shall work under the overall guidance of the said Committee.
- 6.4.3 Monitoring Cell on Ragging:- If the institution is an affiliating university, it shall have a Monitoring Cell on Ragging to coordinate with the institutions affiliated to it by calling for reports from the Heads of such institutions regarding the activities of the Anti-Ragging Committees, Squads, and Mentoring Cells, regarding compliance with the instructions on conducting orientation programmes, counseling sessions, etc., and regarding the incidents of ragging, the problems faced by wardens and other officials, etc. This Cell shall also review the efforts made by such institutions to publicize anti-ragging measures, cross-verify the receipt of undertakings from candidates/students and their parents/guardians every year, and shall be the prime mover for initiating action by the university authorities to suitably amend the Statutes or Ordinances or Bye-laws to facilitate the implementation of anti ragging measures at the level of the institution.

6.5 Other measures:-

- 6.5.1 The Annexures mentioned in sub-clauses 6.1.4, 6.1.5 and 6.1.7 of these Regulations shall be furnished at the beginning of each academic year by every student, that is, by freshers as well as seniors.



- 6.5.2 The institution shall arrange for regular and periodic psychological counseling and orientation for students (for freshers separately, as well as jointly with seniors) by professional counselors during the first three months of the new academic year. This shall be done at the institution and department/ course levels. Parents and teachers shall also be involved in such sessions.
- 6.5.3 Apart from placing posters mentioned in sub-clause 6.1.9 above at strategic places, the institution shall undertake measures for extensive publicity against ragging by means of audio-visual aids, by holding counseling sessions, workshops, painting and design competitions among students and other methods as it deems fit.
- 6.5.4 If the institution has B.Ed. and other Teacher training programmes, these courses shall be mandated to provide for anti-ragging and the relevant human rights appreciation inputs, as well as topics on sensitization against corporal punishments and checking of bullying amongst students, so that every teacher is equipped to handle at least the rudiments of the counseling approach.
- 6.5.5 Wardens shall be appointed as per the eligibility criteria laid down for the post reflecting both the command and control aspects of maintaining discipline, as well as the softer skills of counseling and communicating with the youth outside the class-room situations. Wardens shall be accessible at all hours and shall be provided with mobile phones. The institution shall review and suitably enhance the powers and perquisites of Wardens and authorities involved in curbing the menace of ragging.
- 6.5.6 The security personnel posted in hostels shall be under the direct control of the Wardens and assessed by them.
- 6.5.7 Private commercially managed lodges and hostels shall be registered with the local police authorities, and this shall be done necessarily on the recommendation of the Head of the institution. Local police, local administration and the institutional authorities shall ensure vigil on incidents that may come within the definition of ragging and shall be responsible for action in the event of ragging in such premises, just as they would be for incidents within the campus. Managements of such private hostels shall be responsible for not reporting cases of ragging in their premises.
- 6.5.8 The Head of the institution shall take immediate action on receipt of the recommendations of the Anti-Ragging Squad. He/ She shall also take action suo motto if the circumstances so warrant.
- 6.5.9 Freshers who do not report the incidents of ragging either as victims or as witnesses shall also be punished suitably.
- 6.5.10 Anonymous random surveys shall be conducted across the 1st year batch of freshers every fortnight during the first three months of the academic year to verify and cross-check whether the campus is indeed free of ragging or not. The institution may design its own methodology of conducting such surveys.



- 6.5.11 The burden of proof shall lie on the perpetrator of ragging and not on the victim.
- 6.5.12 The institution shall file an FIR with the police / local authorities whenever a case of ragging is reported, but continue with its own enquiry and other measures without waiting for action on the part of the police/ local authorities. Remedial action shall be initiated and completed within the one week of the incident itself.
- 6.5.13 The Migration / Transfer Certificate issued to the student by the institution shall have an entry, apart from those relating to general conduct and behaviour, whether the student has been punished for the offence of committing or abetting ragging, or not, as also whether the student has displayed persistent violent or aggressive behaviour or any inclination to harm others.
- 6.5.14 Preventing or acting against ragging shall be the collective responsibility of all levels and sections of authorities or functionaries in the institution, including faculty, and not merely that of the specific body/ committee constituted for prevention of ragging.
- 6.5.15 The Heads of institutions other than universities shall submit weekly reports to the Vice-chancellor of the university the institution is affiliated to or recognized by, during the first three months of new academic year and thereafter each month on the status of compliance with anti-ragging measures. The Vice Chancellor of each university shall submit fortnightly reports of the university, including those of the Monitoring Cell on Ragging in case of an affiliating university, to the Chancellor.
- 6.5.16 Access to mobile phones and public phones shall be unrestricted in hostels and campuses, except in class-rooms, seminar halls, library etc. where jammers shall be installed to restrict the use of mobile phones.

6.6 Measures for encouraging healthy interaction between freshers and seniors:-

- 6.6.1 The institution shall set up appropriate committees including the course-in-charge, student advisor, Warden and some senior students to actively monitor, promote and regulate healthy interaction between the freshers and senior students.
- 6.6.2 Freshers' welcome parties shall be organized in each department by the senior students and the faculty together soon after admissions, preferably within the first two weeks of the beginning of the academic session, for proper introduction to one another and where the talents of the freshers are brought out properly in the presence of the faculty, thus helping them to shed their inferiority complex, if any, and remove their inhibitions.
- 6.6.3 The institution shall enhance the student-faculty interaction by involving the students in all matters of the institution, except those relating to the actual processes of evaluation and of faculty appointments, so that the students shall feel that they are responsible partners in managing the



affairs of the institution and consequently the credit due to the institution for good work/ performance is due to them as well.

7. Measures at the UGC/ Statutory/ Regulatory body level:-

7.1 Regulatory measures:-

- 7.1.1 The UGC and other Statutory /Regulatory bodies shall make it mandatory for the institutions to compulsorily incorporate in their 'Prospectus' the directions of the Supreme Court and/or the Central or State Governments with regard to prohibition and consequences of ragging, and that non-compliance with the directives against ragging in any manner whatsoever shall be considered as lowering of academic standards by the erring institution making it liable for appropriate action.
- 7.1.2 The UGC (including NAAC and UGC Expert Committees visiting institutions for various purposes) and similar Committees of other Statutory/Regulatory bodies shall cross-verify that the institutions strictly comply with the requirement of getting the undertakings from the students and their parents/ guardians as envisaged under these Regulations.
- 7.1.3 The UGC and other funding bodies shall make it one of the conditions in the Utilization Certificate for sanctioning any financial assistance or aid to the institution under any of the general or special schemes that the institution has strictly complied with the anti-ragging measures and has a blemish-less record in terms of there being no incidents of ragging during the period pertaining to the Utilization Certificate.
- 7.1.4 The NAAC and other accrediting bodies shall factor in any incident of ragging in the institution while assessing the institution in different grades.

7.2 Incentives for curbing ragging:-

- 7.2.1 The UGC shall consider providing special/ additional annual financial grants-in-aid to those eligible institutions which report a blemish-less record in terms of there being no incidents of ragging.
- 7.2.2 The UGC shall also consider instituting another category of financial awards or incentives for those eligible institutions which take stringent action against those responsible for incidents of ragging.
- 7.2.3 The UGC shall lay down the necessary incentive for the post of Warden in order to attract the right type of eligible candidates, and motivate the incumbents.

7.3 Monitoring mechanism to ensure compliance:-



Apart from the monitoring mechanism built in under different sub-clauses of these Regulations, there shall also be the following monitoring mechanism:

7.3.1 The UGC shall constitute an Inter-Council Committee for prevention of Ragging consisting of representatives of the AICTE, the IITs, the NITs, the IIMs, the MCI, the DCI, the NCI, the ICAR and such other bodies which have to deal with higher education to coordinate and monitor the anti-ragging movement across the country and to make certain policy decisions. The said Committee shall meet at least twice a year in the normal course.

7.3.2 The UGC shall also have an Anti-Ragging Cell within the Commission as an institutional mechanism to provide secretarial support for collection of information and monitoring, and to coordinate with the State level and university level Committees for effective implementation of anti-ragging measures.

8 Punishments:-

8.1 At the institution level:-

Depending upon the nature and gravity of the offence as established by the Anti-Ragging Committee of the institution, the possible punishments for those found guilty of ragging at the institution level shall be any one or any combination of the following:

- 8.1.1 Suspension from attending classes and academic privileges
- 8.1.2 Withholding/ withdrawing scholarship/ fellowship and other benefits
- 8.1.3 Debarring from appearing in any test/ examination or other evaluation process
- 8.1.4 Withholding results
- 8.1.5 Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament, youth festival, etc.
- 8.1.6 Suspension/ expulsion from the hostel
- 8.1.7 Cancellation of admission
- 8.1.8 Rustication from the institution for period ranging from 1 to 4 semesters
- 8.1.9 Expulsion from the institution and consequent debarring from admission to any other institution for a specified period
- 8.1.10 Fine ranging between Rupees 25,000/- and Rupees 1 lakh
- 8.1.11 Collective punishment: When the persons committing or abetting the crime of ragging are not identified, the institution shall resort to collective punishment.

8.2 At the university level in respect of institutions under it:-

If an institution under a university (being constituent of, affiliated to or recognized by it) fails to comply with any of the provisions of these Regulations



and fails to curb ragging effectively, the university may impose any one or any combination of the following penalties on it:

- 8.2.1 Withdrawal of affiliation/ recognition or other privileges conferred on it
- 8.2.2 Prohibiting such institution from presenting any students then undergoing any programme of study therein for the award of any degree/diploma of the university
- 8.2.3 Withholding grants allocated to it by the university, if any
- 8.2.4 Withholding any grants channellised through the university to the institution
- 8.2.5 Any other appropriate penalty within the powers of the university.

8.3 At the appointing authority level:-

The authorities of the institution, particularly the Head of the institution, shall be responsible to ensure that no incident of ragging takes place in the institution. In case any incident of ragging takes place, the Head shall take prompt and appropriate action against the person(s) whose dereliction of duty lead to the incident. The authority designated to appoint the Head shall, in its turn, take prompt and appropriate action against the Head.

8.4 At the UGC/Statutory/Regulatory body level:-

If an institution fails to curb ragging, the UGC/Statutory/Regulatory body concerned may impose any one or any combination of the following penalties on it:

- 8.4.1 Delisting the institution from section 12B of the UGC Act or any similar provision in the Act of the Statutory/Regulatory body concerned
- 8.4.2 Withholding any grants allocated to it
- 8.4.3 Declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programmes of the UGC/Statutory/ Regulatory body concerned
- 8.4.4 Declaring that the institution does not have the minimum academic standards and warning the potential candidates for admission accordingly through public notice and posting on the UGC Website/ Website of the Statutory/Regulatory body concerned.
- 8.4.5 Taking such other action within its powers as it may deem fit and impose such other penalties as provided till such time as the institution achieves the objective of curbing ragging.
- 8.4.6 Collaborating with one another to work out other possible deterrents.



-:0:-

ANNEXURE I, Part I

UNDERTAKING BY THE CANDIDATE/STUDENT

1. I, _____
S/o. D/o. of Mr./Mrs./Ms. _____
have carefully read and fully understood the law prohibiting ragging and the
directions of the Supreme Court and the Central/State Government in this regard.



2. I have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, and have carefully gone through it.
3. I hereby undertake that
 - I will not indulge in any behavior or act that may come under the definition of ragging,
 - I will not participate in or abet or propagate ragging in any form,
 - I will not hurt anyone physically or psychologically or cause any other harm.
4. I hereby agree that if found guilty of any aspect of ragging, I may be punished as per the provisions of the UGC Regulations mentioned above and/or as per the law in force.
5. I hereby affirm that I have not been expelled or debarred from admission by any institution.

Signed this _____ day of _____ month of _____ year

Signature

Name:

Address:

ANNEXURE I, Part II

UNDERTAKING BY PARENT/GUARDIAN

1. I, _____
F/o. M/o. G/o _____
have carefully read and fully understood the law prohibiting ragging and the directions of the Supreme Court and the Central/State Government in this



regard as well as the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009.

2. I assure you that my son/ daughter/ ward will not indulge in any act of ragging.
3. I hereby agree that if he/she is found guilty of any aspect of ragging, he/she may be punished as per the provisions of the UGC Regulations mentioned above and/or as per the law in force.

Signed this _____ day of _____ month of _____ Year

Signature

Name:

Address:





University Grants Commission

Decisions agreed upon in the Central Inter-Council/Statutory Bodies, State Councils of Higher Education and Education Secretary of State Government in the meeting held 13th April, 2009 in UGC, New Delhi.

The following were present:-

UGC:

Prof. Sukhadeo Thorat, Chairman

In Chair.

Dr. R.K. Chauhan, Secretary.

Dr. C.S. Meena, JS (CPP-II).

Shri V.K. Jaiswal, US (CPP-II).

Members of the UGC Committee for preparation of Regulations:-

Prof. K.P.S Unni

Dr. R.P. Gangurde

Prof. Virbala Aggarwal

Representatives of the Statutory Councils:

Medical Council Of India

National Council of Teacher Education

Indian Council of Agricultural Research

Distant Educational Council

Dental Council of India

Pharmacy Council of India

Bar Council of India

Representative of the State Governments:-

A.P. Council of Higher Education

H.P. Government,

Punjab Government ,

U.P. Government

Following decisions were taken:-

- a) The participants discussed the Draft Regulations for Prevention of Ragging and made various suggestions. Most of the suggestions were agreed and it was decided that these suggestions would be incorporated in the Regulations after taking into account the legal provisions. The UGC expert committee may do the same preferably by 20th April, 2009.
- b) The various Councils generally agreed with draft Regulations and decided that they would frame their Regulations taking the UGC Regulations as the base and only add some additional provisions to address the specific issues peculiar to each one of them.



13/4/09
DS/PP/II

13/04/09


13/4/09
US (CPP-II)


13/4/09
US (CPP-II)



- c) The Council agreed that they will make effort to finalize their Regulations latest by the end of May duly approved by their respective statutory bodies.
- d) The members agreed to constitute an Inter-Council Committee for prevention of Ragging to address the issue relating to ragging which are of national importance and to sort out the issue of overlapping and cross cutting issues. The Committee will meet at least twice a year.
- e) The UGC will finalize the Regulations by next week and send to various councils for follow up action at their end. These will also be placed on the UGC Website for the convenience of the Councils.
- f) The UGC would get the approval of the Commission by circulation, which is expected by the end of April, 2009.
- g) The participants discussed the Monitoring mechanism proposed by Edcil and the presentation made by Prof. Raj Kachroo. The Ed.Cil was requested to finalize the same duly approved by the Ministry of HRD urgently so that the mechanism could also be brought to the notice of Universities and colleges along with these Regulations. The Ed. Cil would sent the communication to all the statutory bodies/councils for the monitoring mechanism agreed by it.
- h) These Regulations would be inplace before the commencement of the next academic year in June 2009.

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.


(R. K. CHAUHAN)
13.11.2009


(SUKHADEO THORAT)



**UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADLURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110002**

F.1-16/2007(CPP-II)

List of participants of meeting of UGC Expert Committee on Regulation to curb the menace of ragging in Higher Educational Institutions-2009 held in UGC Office, New Delhi on 13.4.2009 with State/UT Higher Education Secretary, Professional Councils, State Council of Higher Education

Members UGC Expert Committee

1. Prof. KPS Unny
Former Registrar, JNU, Brindavan
Near DP office, West Yakkara Road
Palakkad-678014 (Kerala)
Phone 09895865526, kpsunny39@gmail.com
 2. Prof. Virbala Aggarwal
H.P. Univ.
Shimla-171005
Phone 09418168234
 3. Dr. R.P. Gangurde,
Former Addl. Secretary, UGC
C-13/26, Sector 38, Kendriya Vihar
Nerul, New Mumbai-400706
 4. Prof. M.Z. Khan
UGC Consultant
B-59, City Apartments
Vasundhara Enclave
Delhi-110096
- Special invitee

Special invitee

Mr. Raj Kachroo
Aman Movement

Present (UGC)

1. Prof. S.K. Thorat, Chairman, UGC
2. Dr. R.K. Chauhan, Secretary, UGC
3. Dr. C.S. Meena, Joint Secretary, UGC
4. Sh. A.N. Sharma, Deputy Secretary UGC
5. Sh. V.K. Jaiswal, Under Secretary, UGC
6. Smt. Lalitha Ganeshan, S.O., UGC



Professional Councils

1. Dr. Prem Kumar,
Additional Secretary
Medical Council of India
Pocket- 14, Sector-8
Dwarka Phase-1
New Delhi-110077
2. Prof. SVS Choudhary
Vice Chairman
National Council for Teacher Education
Hans Bhavan, Wing II,
1, Bahadursha Zafar Marg
New Delhi-110002
3. Shri C.L. Bhatia
Consultant
Dental Council of India, Aiwan E Galib Marg
Kotla Road
Temple Lane
New Delhi-110002
4. Shri Shiv Kumar
Section Officer
Dental Council of India, Aiwan E Galib Marg
Kotla Road
Temple Lane
New Delhi-110002
5. Ms. Archana Mudgal
Pharmacy Council of India
Kotla Road, Aiwan E Ghalib Marg
New Delhi-110002
Phone 23239184
6. Sh. J.R. Sharma
Joint Secretary
Bar Council of India
21, Rouse Avenue, Institutional Area
New Delhi-110002



7. Sh. S.K.Mitra
Deputy Secretary (Education)
Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110114
Phone 25848033, Sujitkmitra@gmail.com

8. Dr. S.S.Bisht
CSO
Indira Gandhi National Open University
New Delhi-110068
Phone: 9868106047, 29533237, 29572121 (O)

9. Sh. D .Singh
Director
Edcil , India Ltd., Noida
Phone- 0120-2512008, 9971409065

State Council of Higher Education

1. Prof. K.C.Reddy
Chairman
Andhra Pradesh State Council of Hr. Education
Opposite Mahavir Hospital
Masab Tank, Hyderabad-500028
Phone 9866726222, 040- 23417030

State Education Secretary

1. Dr. Narinder Dhillon
DPI College, Punjab
Phone- 0172-2703549, 9814085651

2. Shri P.C.Dhiman
Secretary (Education Dept)
Govt. of Himachal Pradesh
H.P. Secretariat, Shimla-171002

3. Sh. Prabhat Sinha
Spl. Secretary
Dept. of Higher Education
Govt. of U.P., Lucknow
Phone- 09415171471, 0522-2238601

College

4. Dr. Vijay Shanker
Principal
Govt. P.G.College, Badalpur
GB Nagar, U.P.
Phone: 9873885480
Shankerfiji@yahoo.co.in



Rayat Shikshan Sanstha's
Karmaveer Bhauro Patil College, Vashi
[Autonomous College]

Grievance Redress cell

(Anti-ragging)

2022-23

Index

Sr.No	Contents	Document No
1	Annual report	KBP/GRC/AR/1
2	Year End Meeting(notice , minutes)	KBP/GRC/YEM/2
3	Monthly reports	KBP/GRC/MR/3
4	Year Plan Meeting(notice , minutes)	KBP/GRC/N/4
5	Year Plan	KBP/GRC/YP/5
6	Student Notices	KBP/GRC/SN/6
7	GRC on Website	KBP/GRC/WEB/7
8	Grievance Redress cell mechanism	KBP/GRC/M/8
9	Committee members and scope	KBP/GRC/CMS/9

**Rayat Shikshan Sanstha's
KARMAVEER BHAURAO PATIL COLLEGE
VASHI SECTOR -15, NAVI MUMBAI 400 703
(Autonomous College)**


**GRIEVANCE REDRESS CELL
(Anti-ragging and Sexual harassment Redress)
[TEACHING, NON-TEACHING & STUDENTS]
COMMITTEE**

(2022-23)


Year Report 2022-23

1. We Continued with online portal to register Grievances on college website
<https://www.kbpsollegevash.edu.in/>
Link for Grievance, Ragging .ICC & Suggestions
<https://docs.google.com/forms/d/1OoojewLwL6TUtyzMNOVP-qJaL2GMluq1Ry9tTX6oPI0/edit>
2. Prepared Year plan 2022-23
3. Informed all students, faculty and non-teaching members about Grievance redress cell through general notices & website.

The cell is working for redressing all the grievances and functions to look in Sexual Harassment Redress & ragging cases. No case was registered No Cases of Ragging and ICC were reported or observed in the academic year 2022-23


Mr.S.A.Gharge
Member Secretary
CGRC


Dr Harsha Goyal
Chairman
Internal Complaint Cells


Dr.S.S.Nayak
Chairman CGRC
Principal KBP College




Rayat Shikshan Sanstha's
KARMAVEER BHAURAO PATIL COLLEGE
VASHI SECTOR -15, NAVI MUMBAI 400 703
(Autonomous College)
GRIEVANCE REDRESS CELL
(Anti-ragging)
(2022-23)


Year Report 2022-23

1. Continued online portal on website to register Grievances.
2. Prepared Year plan 2022-23
3. Informed all students, faculty and non-teaching members about Grievance redress cell through general notices & website.
4. All records are available

The cell is working for redress all grievances and functions to look in grievances & ragging cases. No cases were reported either on website portal or observed in the premises for academic year 2022-23


Mr.S.A.Gharge
Member Secretary
CGRC




Dr.S.S.Nayak
Chairman CGRC
Principal K BP College

Rayat Shikshan Sanstha's
KARMAVEER BHAURAO PATIL COLLEGE
VASHI SECTOR -15, NAVI MUMBAI 400 703
(Autonomous College)
GRIEVANCE REDRESS CELL
(Anti-ragging)
(2022-23)

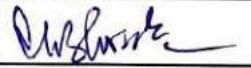

Date: 18 Mar 2023

Notice


All the following are hereby informed to be present for a meeting to discuss the working and Annual report for the academic year 2022-23. The meeting venue is Principal cabin on 23 Mar 2023 at 3.30pm.

Agenda

1. Discuss the Working of CGRC as per University Guidelines regarding CGRC & its implementation.
2. Functioning of CGRC
3. Year Report 2022-23
4. Any other with permission of chair.

Sr. No	Name	Mobile No	E-mail	Sign
1	Mr.C.D.Bhosale	9221765539	cdbhosale@kbpcollegevashi.edu.in	
2	Mr.S.A.Gharge	9869158538	sagcharge@kbpcollegevashi.edu.in	




Dr.S.S.Nayak
Principal
KBP College, Vashi.

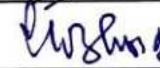
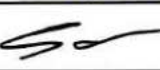
Rayat Shikshan Sanstha's
KARMAVEER BHAURAO PATIL COLLEGE
VASHI SECTOR -15, NAVI MUMBAI 400 703
(Autonomous College)
GRIEVANCE REDRESS CELL
(Anti-ragging)
(2022-23)

Minutes of Meeting Year End

Date: 23-03-2023

A meeting of following members was called to order on 23 Mar 2023 at 3:30 pm by Hon, Principal (Dr.S.S.Nayak)

All the following were present for a meeting to discuss your report of CGRC for the academic year 2022-23.

Sr. No	Name	Designation	Signature
1	Dr.S.S.Nayak	Chairman	
2	Mr.C.D Bhosale	Member	
3	Mr.S.A. Gharge	Member Secretary	

Dr. S.S.Nayak (Principal K.B.P.College Vashi) extended warm welcome to all the members

Minutes

Reading of Agenda

- Motion from Dr.S.S.Nayak: To approve the working for 23 Mar 2023

Vote: All in favor

Resolved: **Motion carried.**

Agenda for the meeting on 23 Mar 2023 approved without modification

Business

Motion 1: Discuss the Working of CGRC as per University Guidelines regarding CGRC & its implementation..



Discussion: The CGRC work was as per guidelines in accordance with University circular no DSD/05/of 2019.

Vote: All in favor

Resolved: **Motion carried**

Motion 2: The functioning of CGRC

Discussion: The functioning of CGRC was as per Guideline by University of Mumbai Department of Students' Development Procedure and Directives for functioning of College Grievance Redress cell (CGRC)

Vote: All in favor.

Resolved: **Motion carried**

Motion 3: Year Report 2022-23

1. Continued online portal on website to register Grievances.
2. Prepared Year plan 2022-23
3. Informed all students, faculty and non-teaching members about Grievance redress cell through general notices & website.
4. All records are available

The cell is working for redress all grievances and functions to look in grievances & ragging cases. No cases were reported either on website portal or observed in the premises academic year 2022-23

Vote: All in favor.

Resolved: **Motion carried**

Vote of thanks was proposed by Mr S.A.Gharge

Meeting was adjourned at 4:00 pm



Mr.S.A.Gharge
Member Secretary



Mr.C.D.Bhosale
Member CGRC



Dr.S.S.Nayak
Chairman CGRC
Principal KBP College



Rayat Shikshan Sanstha's
Karmaveer Bhaurao Patil College, Vashi

Grievance Redress cell

(Anti-ragging)

2022-23.

Date: 14 July 2022

Date: 29 July 2022

Monthly Report

There was no Grievance found in any of the boxes and none was presented. There was no suggestion, grievance, ragging or sexual harassment reported through college website link


Secretary,
Grievance Redress cell
(Chairman Anti-ragging and member ICC.)


PRINCIPAL
KARMAVEER BHAURAO PATIL COLLEGE
VASHI, NAVI MUMBAI - 400 703,



Rayat Shikshan Sanstha's
Karmaveer Bhaurao Patil College, Vashi

Grievance Redress cell

(Anti-ragging)

2022-23.

Date: 13 Aug 2022

Date: 30 Aug 2022

Monthly Report

There was no Grievance found in any of the boxes and none was presented. There was no suggestion, grievance, ragging or sexual harassment reported through college website link



Secretary,
Grievance Redress cell
(Chairman Anti-ragging and member ICC.)



PRINCIPAL
KARMAVEER BHAURAO PATIL COLLEGE
VASHI, NAVI MUMBAI - 400 703

Rayat Shikshan Sanstha's
Karmaveer Bhaurao Patil College, Vashi

Grievance Redress cell

(Anti-ragging)

2022-23.

Date: 14 Oct 2022

Date: 22 Oct 2022

Monthly Report

There was no Grievance found in any of the boxes and none was presented. There was no suggestion, grievance, ragging or sexual harassment reported through college website link



Secretary,
Grievance Redress cell
(Chairman Anti-ragging and member ICC.)




PRINCIPAL
KARMAVEER BHURAO PATIL COLLEGE
VASHI, NAVI MUMBAI - 400 703.

Rayat Shikshan Sanstha's
Karmaveer Bhaurao Patil College, Vashi

Grievance Redress cell

(Anti-ragging)


2022-23.

Date: 16 Nov 2022

Date: 29 Nov 2022

Monthly Report

There was no Grievance found in any of the boxes and none was presented. There was no suggestion, grievance, ragging or sexual harassment reported through college website link


Secretary,
Grievance Redress cell
(Chairman Anti-ragging and member ICC.)




PRINCIPAL
KARMAVEER BHURAO PATIL COLLEGE
VASHI, NAVI MUMBAI - 400 703.

Rayat Shikshan Sanstha's
Karmaveer Bhaurao Patil College, Vashi

Grievance Redress cell

(Anti-ragging)

2022-23.

Date: 14 Jan 2023

Date: 24 Jan 2023

Monthly Report

There was no Grievance found in any of the boxes and none was presented. There was no suggestion, grievance, ragging or sexual harassment reported through college website link



Secretary,
Grievance Redress cell
(Chairman Anti-ragging and member ICC.)



PRINCIPAL
KARMAVEER BHAURAO PATIL COLLEGE
VASHI, NAVI MUMBAI - 400 703.

Rayat Shikshan Sanstha's
Karmaveer Bhaurao Patil College, Vashi

Grievance Redress cell

(Anti-ragging)

2022-23.

Date: 15 Feb 2023

Date: 28 Feb 2023

Monthly Report

There was no Grievance found in any of the boxes and none was presented. There was no suggestion, grievance, ragging or sexual harassment reported through college website link


Secretary,
Grievance Redress cell
(Chairman Anti-ragging and member ICC.)




PRINCIPAL
KARMAVEER BHURAO PATIL COLLEGE
VASHI, NAVI MUMBAI - 400 703.

Rayat Shikshan Sanstha's
Karmaveer Bhaurao Patil College, Vashi

Grievance Redress cell

(Anti-ragging)

2022-23.

Date: 16 Mar2023

Date: 29 Mar 2023

Monthly Report

There was no Grievance found in any of the boxes and none was presented. There was no suggestion, grievance, ragging or sexual harassment reported through college website link.



Secretary,

Grievance Redress cell

(Chairman Anti-ragging and member ICC.)



PRINCIPAL

KARMAVEER BHAURAO PATIL COLLEGE

VASHI, NAVI MUMBAI - 400 703.

**Rayat Shikshan Sanstha's
KARMAVEER BHAURAO PATIL COLLEGE
VASHI SECTOR -15, NAVI MUMBAI 400 703
(Autonomous College)
GRIEVANCE REDRESS CELL
(Anti-ragging)
(2022-23)**



Date: 11 Aug 2022

Notice


All the following are hereby informed to be present for a meeting to discuss the working and year plan for the academic year 2022-23. The meeting venue is Principal cabin on 12 Aug 2022 at 3.30pm.

Agenda

1. Discuss the University Guidelines regarding CGRC & Ragging.
2. Review of online portal on website to register Grievances.
3. Functioning of CGRC
4. Year plan 2022-23
5. Any other

Sr. No	Name	Mobile No	E-mail	Sign
1	Mr.C.D.Bhosale	9221765539	cdbhosale@kbpcollegevashi.edu.in	
2	Mr.S.A.Gharge	9869158538	sagharge@kbpcollegevashi.edu.in	




Dr.S.S.Nayak
Principal
K.B.P College, Vashi

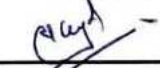
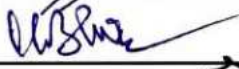

Rayat Shikshan Sanstha's
KARMAVEER BHAURAO PATIL COLLEGE
VASHI SECTOR -15, NAVI MUMBAI 400 703
(Autonomous College)
GRIEVANCE REDRESS CELL
(Anti-ragging)
(2022-23)

Minutes of meeting

Date: 12 Aug 2022

A meeting of following members was called to order on 12 Aug 2022 at 3:30 pm by Hon, Principal (Dr.S.S.Nayak).

All the following were present for a meeting to discuss the Agenda and year plan of CGRC for the academic year 2022-23.

Sr. No	Name	Designation	Signature
1	Dr.S.S.Nayak	Chairman	
2	Mr.C.D Bhosale	Member	
3	Mr.S.A. Gharge	Member Secretary	

Dr. S.S.Nayak (Principal K.B.P.College Vashi] extended warm welcome to all the members.

Minutes

Reading of Agenda:

- Motion from Dr.S.S.Nayak: To approve the agenda for 12 Aug 2022.

Vote: All in favor.

Resolved: **Motion carried.**

Agenda for the meeting on 12 Aug 2022 approved without modification



Business:

Motion 1: Constitute College Grievance redress Cell (CGRO)

The CGRC was constituted as follows

Chairman : Hon Principal Dr.S.S Nayak
Member : Vice Principal Mr.C.D.Bhosale
Member Secretary : Mr. S.A. Gharge.

Vote All in favor

Resolved: Motion carried.

Motion 2: Discuss the University Guidelines regarding CGRC Discussion: The CGRC should be as per guidelines made in accordance with University circular no DSD/15 (of 2019).

Vote: All in favor

Resolved: Motion carried

Motion 3: Guidelines for online portal on website to register

Grievances

Discussion Portal for registration was to be continued as per University circular no DSD/05/of 2019 with consultation of Web site In charge Miss Samiksha from IT Department

Vote: All in favor

Resolved: Motion carried

Motion 4: The functioning of CGRC

Discussion The functioning of CGRC will be as per Guideline by University of Mumbai Department of Students' Development as per Procedure and Directives for functioning of College Grievance Redress cell (CGRC)

Vote: All in favor.

Resolved: Motion carried



Motion 4: Year plan 2022-23

Discussion

1. To continue with portal on college website
2. To upload Information on functioning of CCRC portal
3. To give Wide publicity among students
4. To receive the applications of the students from the portal/boxes available on the website/premises of college/ Institute and process them further.(Once in every month).
5. To attend all applications mating to the grievances of the students.
6. To entertain and consider the grievances of the students' college employees. It may hear the student's in person by giving opportunities of hearing.
7. To hear all the concerned parties and semi grievances as early as possible.
8. To counsel the students whenever necessary to resolve their grievances.
9. To give advice to the students through correspondence.
10. To prepare and submit the recommendations relating to redress of grievances to the concerned.
11. To prepare Minutes and Action Taken Report of the meeting of CGRC and Antiragging.
12. To prepare Annual Report regarding working of the CGRC and Anti ragging.

Vote all in favor

Resolved: **Motion carried**

Vote of thanks was proposed by Mr. S.A.Gharge

Meeting was adjourned at 4:30 pm



Mr.S.A.Gharge
Member Secretary
CGRC



Mr. C.D. Bhosale
Member
CGRC



Dr.S.S.Nayak
Chairman CGRC
Principal KBP College



Rayat Shikshan Sanstha's

Karmaveer Bhaurao Patil College, Vashi

[Autonomous College]

College Grievance Redress cell


(Anti Ragging)


(2022-2023)

Perspective Year plan 2022-2023

Date: 12/08/2022

1. To ensure Implementation of guidelines of statutory / regulatory bodies i: e Maharashtra Govt. Part 4 Serial no 67, University Circular No DSD/05/ Of 2019, Rayat Shikshan Sanstha Directives & Indian Government regarding Prevention prohibition & Redress Act 2013.
2. To give Wide publicity among students
3. To receive the applications of the students from the portal/boxes available on the Website/ premises of College)/ Institute and process them further.
4. To attend all applications relating to the grievances ragging of the students.
5. To entertain and consider the grievances of the students college employee. It may hear the student's in person by giving opportunities of hearing.
6. To hear all the concerned parties and settle grievances within a fortnight
7. To counsel the students whenever necessary to resolve their grievances.
8. To give advice to the students through correspondence.
9. To prepare and submit the recommendations relating to the redress of grievances to the concerned.
10. To consider and submit recommendations and suggestion in respect of reforms in the working of various sections/units/departments/cells of the College/Institution relating to the redress of grievances of students.
11. To prepare Minutes and Action Taken Report of the meeting of CGRC
12. To prepare Annual Report regarding working of the CGRC(Antiragging)


Mr.S.A.Gharge
Member Secretary
CGRC


Dr. S.S. Nayak
Chairman CGRC Principal
K.B.P. College, Vashi



Rayat Shikshan Sanstha's
Karmaveer Bhaurao Patil College, Vashi
[Autonomous College]
College Grievance Redress cell
(Anti Ragging)
(2022-2023)

Perspective Year plan 2022-2023

Date: 14/07/2022

1. To ensure Implementation of guidelines of statutory / regulatory bodies i: e Maharashtra Govt. Part 4 Serial no 67, University Circular No DSD/05/ Of 2019, Rayat Shikshan Sanstha Directives & Indian Government regarding Prevention prohibition & Redress Act 2013.
2. To give Wide publicity among students
3. To receive the applications of the students from the portal/boxes available on the Website/ premises of College)/ Institute and process them further.
4. To attend all applications relating to the grievances,ragging of the students.
5. To entertain and consider the grievances of the students college employee. It may hear the student's in person by giving opportunities of hearing.
6. To hear all the concerned parties and settle grievances within a fortnight
7. To counsel the students whenever necessary to resolve their grievances.
8. To give advice to the students through correspondence.
9. To prepare and submit the recommendations relating to the redress of grievances to the concerned.
10. To consider and submit recommendations and suggestion in respect of reforms in the working of various sections/units/departments/cells of the College/Institution relating to the redress of grievances of students.
11. To prepare Minutes and Action Taken Report of the meeting of CGRC
12. To prepare Annual Report regarding working of the CGRC

Mr.S.A.Gharge
Member Secretary
CGRC

Dr. S.S Nayak
Chairman CGRC Principal
K.B.P. College, Vashi



Rayat Shikshan Sanstha's
KARMAVEER BHAURAO PATIL COLLEGE
VASHI SECTOR -15, NAVI MUMBAI 400 703
(Autonomous College)
GRIEVANCE REDRESS CELL
(Anti-ragging)
(2022-23)

Date 04-08-2022

Notice for all students

All the students are hereby informed that Grievance Redress cell has installed Grievance boxes at various locations in college. Please approach the appropriate authority in case you have grievances. If the issue doesn't get solved, kindly put your grievances and suggestions in the boxes. You can also upload your suggestions grievance on

College website <https://www.kbpcollegevashi.edu.in>

Google form:

<https://docs.google.com/forms/d/1OoojewLwL6TUtyzMNOVP-qJaL2GMluq1Ry9tTX6oPI0/edit>



Mr.S.A.Gharge
Member Secretary
Grievance Redress Cell



Dr.S.S.Nayak
Principal
K BP College, Vashi

STUDENTS' GRIEVANCES REDRESSAL CELL

Vision

Promotion and maintenance of conducive environment for students.

Mission

1. Supporting students who are entitled for the services of college.
2. Increase responsiveness and accountability of the officials of the college towards the issues relating to students.
3. Ensuring surety to find out solutions for the grievances raised by the students.

Review of the work done by Grievance cell 2014-2019.

The cell enables the students to express their views and follow grievance procedure according to the rules and regulations of the college.

Students Grievance Cell enquires about the nature of Grievance from the students after conducting orientation about the activities to be conducted by the committee throughout the year.

Staff members from the committee conduct orientation in each class at the beginning of the year.

Oral and written Grievances are collected from the students which are kept confidential.

Nature of complaint includes Grievances regarding facilities provided by the college like classroom, maintenance, canteen, washroom, library etc. Grievances regarding teaching and Non-teaching staff are collected from the students.

Regular meetings with the chairpersons of the committee are conducted on regular basis.

Badges are provided to the student's incharge of Grievance Cell.

After conducting Regular meetings outcomes are kept for approval before the meeting conducted with the principal and IQAC co-ordinators. In these meeting representatives of students also express their views and give some suggestions for solving the problems.

Grievances are redressed without any discrimination.

Committee tries to resolve the Grievances regarding academic and administrative problems within 45 days.

Complaint boxes are installed in which students can put their complaints without mentioning name in order to keep complete secrecy.

This box is opened after every month in the presence of Grievance incharge and students.

Grievances relating to the administrative and teaching staff are informed to the respective staff for improvement through higher authorities.

GAC Information on website

I/c. Principal
Karmaveer Bhaurao Patil College
Vashi, Navi Mumbai - 400 703.



Future Plan

In future Grievance cell will take efforts to resolve more complaints as early as possible.

More awareness will be created among the students through intensive orientation and certificate will be given to the Grievance representative in order to boost their moral.

COLLEGE

- » ABOUT US
- » Awards & Certif
- » Knowledge Resource Center (Library)
- » College Committees
- » Cynahara

QUICK LINKS

- » Home
- » Facilities
- » Academics
- » Admissions
- » Examination
- » Magazine

SUPPORT

- » Grievance Redressal Portal
- » Internal Complaint Committee
- » Int. Ragging
- » Gender Issue Cell
- » Counselling Cell
- » Competitive Exam Cell

GET IN TOUCH

- » Vashi,Thane, Navi Mumbai, Maharashtra 400700
- » +91-022-27661210
- » enquiry@kbpcollegevashi.edu.in

Copyright. All rights reserved. @ Karmaveer Bhaurao Patil College, Vashi (Autonomous)
Designed by Mastersoft



ANNEXURE I
AFFIDAVIT BY THE STUDENT

I, _____ (full name of student with Institute Roll Number)
s/o d/o Mr./Mrs./Ms. _____, having
been admitted to _____ (name of the institution), have
received or downloaded a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher
Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the
provisions contained in the said Regulations.

- 1) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- 2) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the
penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting
ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- 3) I hereby solemnly aver and undertake that
 - a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the
Regulations.
 - b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be
constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- 4) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the
Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or
any law for the time being in force.
- 5) I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country
on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm
that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.
- 6) Along with the above mentioned points I do hereby declare that
 - a) I will obey the code of conduct of the institute and do not indulge in any kind of in-disciplined activity
while in and off the institution campus.
 - b) I will be solely responsible for any kind of accident/mishap caused on account of the above mentioned
clause (6.a).

Declared this ___ day of _____ month of _____ year.

Signature of deponent
Name: _____

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false
and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at _____(place) on this the _____(day) of _____(month), _____(year) .

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the _____(day) of _____(month),
_____ (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

*Note : It is mandatory to submit this affidavit in the above format, if you desire to register for the
forthcoming academic session.*

LINK DOC ON WEBSITE


I/e. Principal
Karmaveer Bhaurao Patil College
Vashi, Navi Mumbai - 400 703.

Application for Redressal of Grievance/s

* Indicates required question

1. 1) First Name of the Student *

2. 2) Middle Name of the Student *

3. 3) Last Name of the Student *

4. 4) Department *

Mark only one oval.

- Sr. College- Arts
- Sr. College- Commerce
- Sr. College- Science
- Sr. College- Self-Finance

5. 5) Residential Address of the Student *

6. 6) Permanent Address of the Student *

7. 7) Email of the Student *

8. 8) Mobile Number of the Student *

9. 9) WhatsApp Number of the Student *

10. 10) Landline Number of the Student (If Any)

11. 11) Faculty *

Mark only one oval.

- Sr. College- Arts
- Sr. College- Commerce
- Sr. College- Science
- Sr. College- Self-Finance

12. 12) Programme of Study *

Mark only one oval.

- UG
- PG
- Ph.D.
- Others (Please Specify)

13. 13) Class *

Mark only one oval.

- B.A.
- B.Com.
- B.Sc.
- B.Sc.CS
- B.Sc.I.T.
- B.A.F/B.B.I/B.M.S
- M.A.
- M.Com.
- M.Sc. Physics
- M.Sc.C.S.
- M.Sc.I.T.
- M.Sc.Maths
- M.Sc.Microbiology
- M.Sc. Chemistry

14. 14) Year of Study *

Mark only one oval.

- First
- Second
- Third

15. 15) Semester *

Mark only one oval.

- I
- II
- III
- IV
- V
- VI

16. 16) Roll No. *

17. 17) PRN No. *

18. 18) P.G./Ph.D. Registration No.

19. 19) Name of the Student/s/Teacher/s / Officer/s / Staff / Section/s / Department/s *
against whom the Complaint is to lodged

Application for Redressal of Grievances

20. 20) Nature of Grievance/s in which Redressal is Sought *

Mark only one oval.

- Suggestions
- Grievance
- Instance of Ragging
- Sexual Harrasment
- Discrimination
- Any other

21. 21) Kindly upload the evidence file of the above *

Files submitted:

22. 22) Kindly upload the Supporting Documents (Identity Proof) *

Files submitted:

Declaration from the Students

23. I/thereby declare that the above information furnished by me/us is true to the best * of my/our knowledge. In case if it is turned false I/We am/are personally responsible for the punishment.

Mark only one oval.

I Agree

24. Date: *

Example: January 7, 2019

FORM ON WEBSITE


I/c. Principal
Karmaveer Bhaurao Patil College
Vashi, Navi Mumbai - 400 703.

**Rayat Shikshan Sanstha's
KARMAVEER BHAURAO PATIL COLLEGE
VASHI SECTOR -15, NAVI MUMBAI 400 703**

**GRIEVANCE REDRESS CELL
(Anti-ragging and Internal Complaint Committee)**

[TEACHING NON-TEACHING & STUDENTS] COMMITTEE

(2022-23)

Grievance Redress Cell Mechanism

Yes, there is a mechanism for Grievance Redress cell (GRC) at the following level

- 1) Grievance Redress Cell for teaching Staff
- 2) Grievance Redress Cell for Non-Teaching Staff
- 3) Grievance Redress Cell for Students

GRC Constituted as under

For Teaching-	Principal is the Chairman Vice Principal as the member Member is Member secretary.
For Non-Teaching-	Principal is the Chairman Vice Principal as the member, One Member from Non teaching Staff
For Students-	Principal is the Chairman Vice Principal as the member, Sr College Faculty is Member secretary

Mechanism for Registration of Grievances

1 Availability of online portal on website to register Grievances on college website

<https://www.kbpcollegevashi.edu.in/>

Link for Grievance <https://docs.google.com/forms/d/1OoojewLwL6TUtyzMNOVP-gJaL2GMluq1Ry9tTX6oPI0/edit>

2. Placement of Grievance/ Suggestion Boxes in various floors Administrative, Library, Main Building

3. All Administrative and Faculty are pro students and note grievances

4. Mentor mentee committee has a great role to play



GRC functions to serve following objectives:

1. To settle dispute if any
2. To create cordial environment and to insist for avoiding differences

The following mechanism is applied for solving the grievances

A) For students:

Separate committee is constituted for handling the grievances of the students. The members of the committee meet twice in the year to discuss grievances of the students. Grievances & suggestion boxes are fixed on each floor of the building and students use to drop their suggestions in the suggestions Box. The suggestion Boxes are opened twice every month
Online grievances are accepted through link in website

Grievances are less from the students due to the following reasons.

1. There are another two committees working at college level namely
 - A) Teacher Parenthood committee
 - B) Student's feedback committee.
 - C) Student's council.
 - D) There are various committees constituted for college administration Chairman of each committee look in to the matter related to students
 - E) Principal. Dr. S.S Nayak is easily available to the students at any time
- The working chairman with the guidance of the chairman does various activities throughout the year

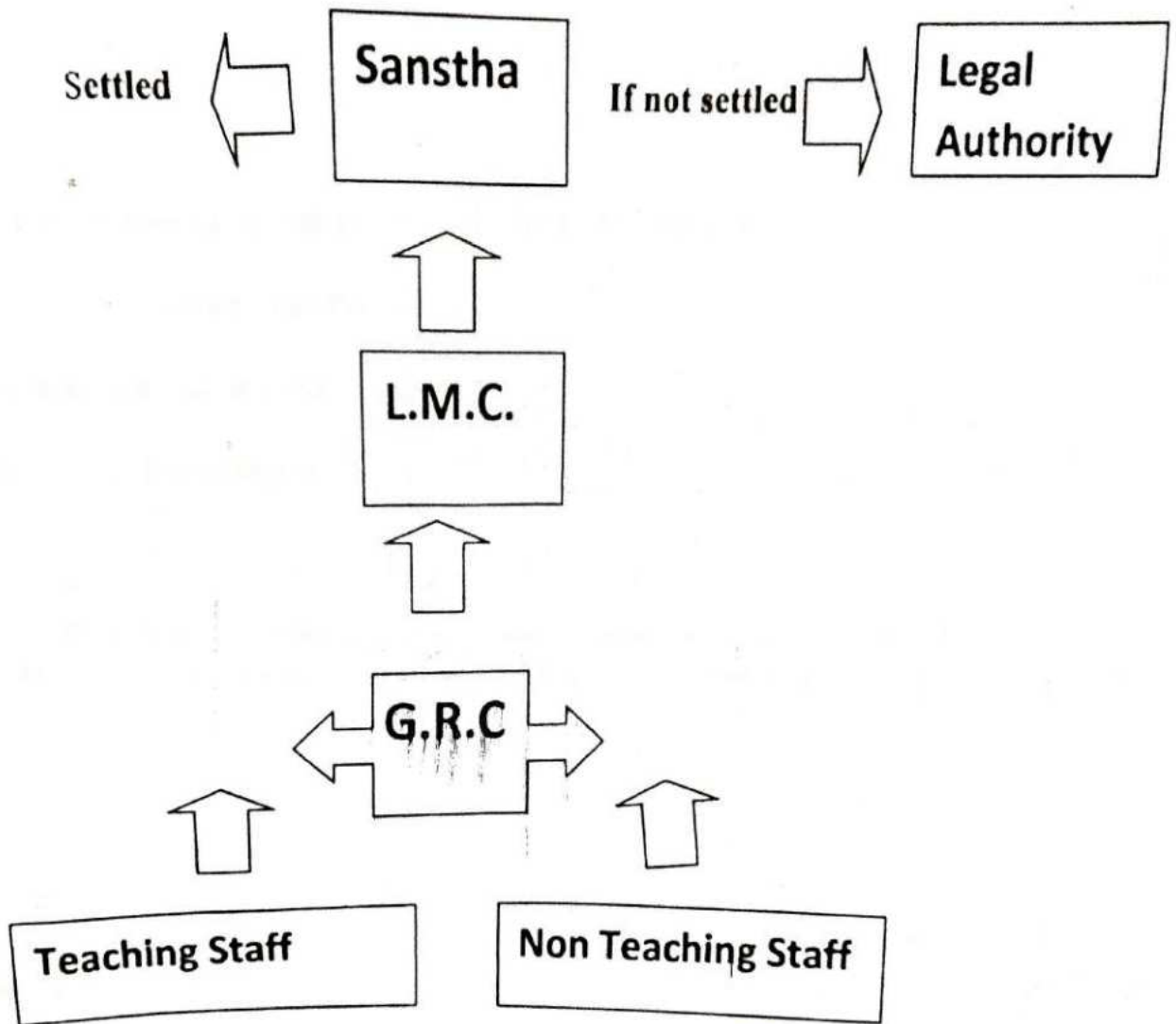
1. Inform all students, faculty and non-teaching members about Grievance redress cell (Anti-ragging) through general notices.
2. Display of all information and Govt, University and Sanstha circulars regarding the above on notice boards and websites.
3. Attend to complaints received in grievance boxes and through link in website
4. Take complaints regarding sexual harassment and ragging on occurrence of instances
5. Grievance and suggestions, if any, of faculty and staff will be collected by the chairman.
6. Grievance and suggestion of parents, if any, will be collected by the chairman.
7. If required, the Grievance Redress cell committee meeting will be conducted on time with kind permission of the Hon. Principal to discuss grievances in the college



Grievance Redress Cell

Mechanism for Settlement of Grievances

B) Teaching & Non-Teaching Staff




Types of Grievances:

- A) Teachers & Teachers
- B) Teachers & College
- C) Principal & Sanstha.


Grievances are less from the Teachers due to the following reasons.

- 1. Internal Complaint Committee.**
- 2. Women Cell. (Gender issue Cell)**
- 3. BUCTU Unit at college level.**

Healthy environment in the institution promotes acceptable solutions to differences and as a result there are no grievances brought formally to the Grievance Redress Cell.


Mr.S.A.Gharge
Member Secretary
CGRC


Dr Harsha Goyal
Chairman
Internal Complaints Cell


I/c. Principal
Dr.S.S.Nayak
Karmaveer Bhaurao Patil College
Chairman CGRC
Vashi, Navi Mumbai - 400 703.
Principal K BP College



**Rayat Shikshan Sanstha's
KARMAVEER BHAURAO PATIL COLLEGE
VASHI SECTOR -15, NAVI MUMBAI 400 703**

**GRIEVANCE REDRESS CELL
(Anti-ragging and Internal Complaint Committee)**

[TEACHING NON-TEACHING & STUDENTS] COMMITTEE

(2022-23)

Grievance Redress Cell Mechanism

Yes, there is a mechanism for Grievance Redress cell (GRC) at the following level

- 1) Grievance Redress Cell for teaching Staff
- 2) Grievance Redress Cell for Non-Teaching Staff
- 3) Grievance Redress Cell for Students

GRC Constituted as under

For Teaching-	Principal is the Chairman Vice Principal as the member Member is Member secretary.
For Non-Teaching-	Principal is the Chairman Vice Principal as the member, One Member from Non teaching Staff
For Students-	Principal is the Chairman Vice Principal as the member, Sr College Faculty is Member secretary

Mechanism for Registration of Grievances

1 Availability of online portal on website to register Grievances on college website

<https://www.kbpcollegevashi.edu.in/>

Link for Grievance <https://docs.google.com/forms/d/1OoojewLwL6TUtyzMNOVP-qJaL2GMluq1Ry9tTX6oPI0/edit>

2. Placement of Grievance/ Suggestion Boxes in various floors Administrative, Library, Main Building

3. All Administrative and Faculty are pro students and note grievances

4. Mentor mentee committee has a great role to play



GRC functions to serve following objectives:

1. To settle dispute if any
2. To create cordial environment and to insist for avoiding differences

The following mechanism is applied for solving the grievances

A) For students:

Separate committee is constituted for handling the grievances of the students. The members of the committee meet twice in the year to discuss grievances of the students. Grievances & suggestion boxes are fixed on each floor of the building and students use to drop their suggestions in the suggestions Box. The suggestion Boxes are opened twice every month Online grievances are accepted through link in website

Grievances are less from the students due to the following reasons.

1. There are another two committees working at college level namely

- A) Teacher Parenthood committee
- B) Student's feedback committee.
- C) Student's council.

D) There are various committees constituted for college administration Chairman of each committee look in to the matter related to students

E) Principal. Dr. S.S Nayak is easily available to the students at any time

The working chairman with the guidance of the chairman does various activities throughout the year

1. Inform all students, faculty and non-teaching members about Grievance redress cell (Anti-ragging) through general notices.

2. Display of all information and Govt, University and Sanstha circulars regarding the above on notice boards and websites.

3. Attend to complaints received in grievance boxes and through link in website

4. Take complaints regarding sexual harassment and ragging on occurrence of instances

5. Grievance and suggestions, if any, of faculty and staff will be collected by the chairman.

6. Grievance and suggestion of parents, if any, will be collected by the chairman.

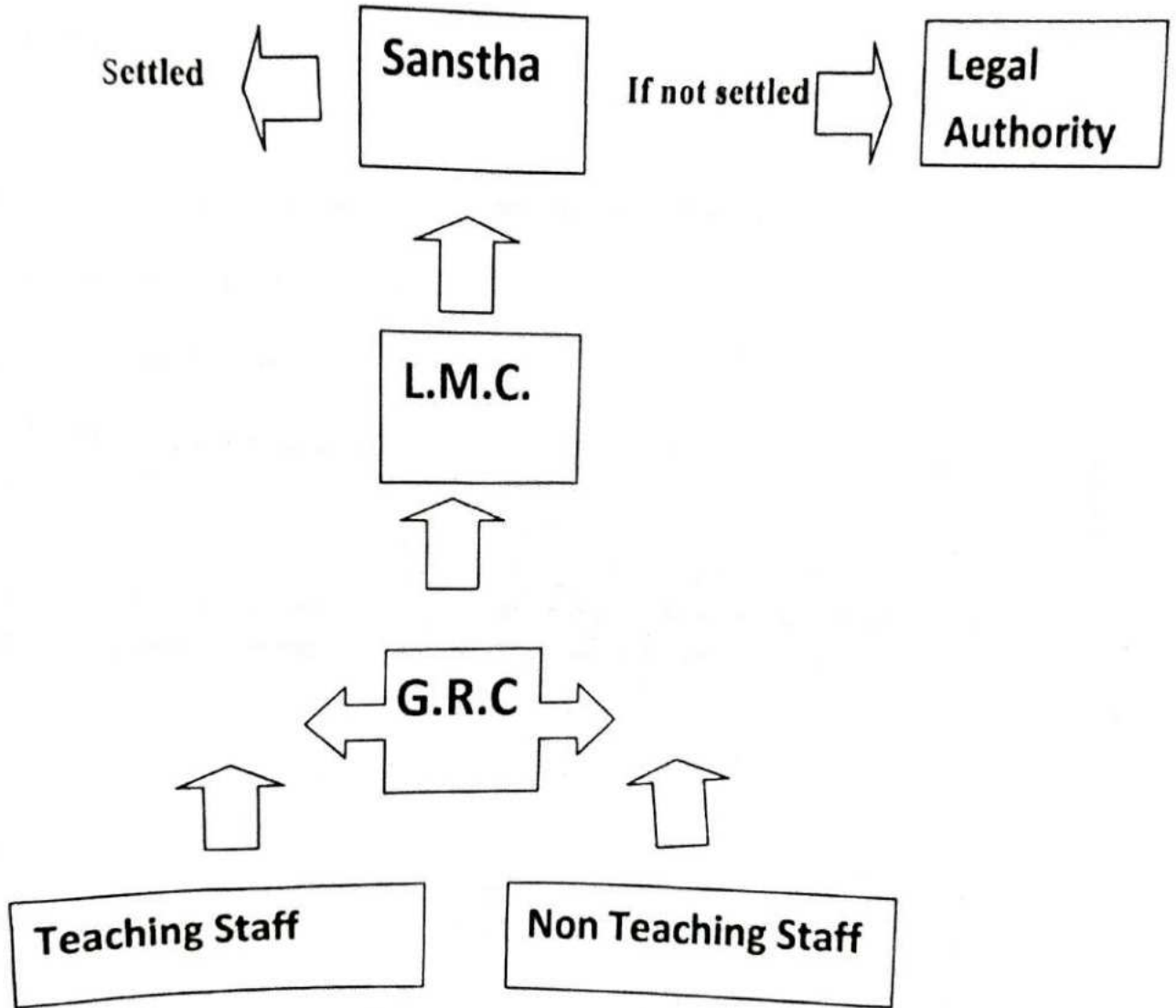
7. If required, the Grievance Redress cell committee meeting will be conducted on time with kind permission of the Hon. Principal to discuss grievances in the college



Grievance Redress Cell

Mechanism for Settlement of Grievances

B) Teaching & Non-Teaching Staff




Types of Grievances:

- A) Teachers & Teachers
- B) Teachers & College
- C) Principal & Sanstha.


Grievances are less from the Teachers due to the following reasons.

- 1. Internal Complaint Committee.**
- 2. Women Cell. (Gender issue Cell)**
- 3. BUCTU Unit at college level.**

Healthy environment in the institution promotes acceptable solutions to differences and as a result there are no grievances brought formally to the Grievance Redress Cell.


Mr.S.A.Gharge
Member Secretary
CGRC


Dr Harsha Goyal
Chairman
Internal Complaints Cell


Dr.S.S.Nayak
Chairman CGRC
Principal K BP College



Rayat Shikshan Sanstha's
Karmaveer Bhaurao Patil College, Vashi
Grievance Redress Cell

(20 - 20)

Date:

To,

Subject: Grievance

Dear Sir / Madam,

This is regarding grievance received on -----

Details are as:-




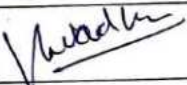
This is for your reference and for taking appropriate redressal. The action taken with date should be conveyed in writing to the chairman.

Chairman,
Grievance Redress Cell



CS
Uc Principal
Principal,
Karmaveer Bhaurao Patil College
Vashi, Navi Mumbai - 400 703.

Form Approved For conveying Grievance
To concerned Authority/ Person.

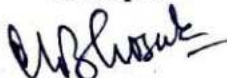
Grievance Redress Cell working committee [Teaching, non-teaching & students] Including Anti-ragging 2022-23				
Sr. No.	Name of faculty member	Department	Position	Sign
1	Mr. S. A. Gharge	Micro	Chairman	
2	Ms. Patil Mrunalini D.	Psychology	Member	
3	Ms. Sonam A Bais	IT	Member	
4	Ms. Vrushali Wadkar	CS	Member	
5	Mr. Dasharath Bhagat	CDC	Member	Informed
6	Ms. Yashodhara Godbole [DCP]	DCP	Member	Informed

Scope of Work [Grievance Redress Cell]:


1. Maintain complaint boxes in the college premises with complaint box through online mode (google form)
2. Inform students and teaching and non-teaching members of the staff about grievance redress cell and its functioning through separate general notices.
3. Attend to complaints received in the complaint boxes once in a month.
4. Take compliance in consultation with Hon. Principal.
5. Follow up the compliance by concerned department/ committee.
6. Conduct at least three meetings [per term] of committee members and maintain record of minutes of the meeting.
7. Submit all the records in a form of file at the end of the year.

Scope of Work [Anti-ragging]:

1. Inform students about existence of anti-ragging committee, anti-ragging laws and punishments in case of offence.
2. Display the above said information on the boards including electronic boards and website. Also, contact numbers of competent authority at the strategic locations.
3. Take note of any complaint of ragging.
4. Take action in case of offence as per the law and in consultation with Hon. Principal.


Mr. C. D. Bhosale
Coordinator, IQAC




Dr. Shubhada Nayak
I/C Principal